



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2012/फाल्गुन 26, 1933

No. 69]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

सं. एफ. 2(13)-बी(डी)/2012.-निम्नलिखित को
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बजट 2012-2013

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण

16 मार्च, 2012

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2012-13 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यह वर्ष पुनरुत्थान में व्यवधान का वर्ष रहा। जब एक वर्ष पूर्व, मैंने बजट प्रस्तुत किया था, हमारे समक्ष अनेक चुनौतियाँ थीं, परन्तु यह अनुभूति भी थी कि विश्व अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। बजट आशा की पहली झलक के बीच प्रस्तुत किया गया था। परन्तु स्थितियाँ आगे चलकर बदल गईं। यूरो जोन में सौंवरन ऋण संकट और गहराया, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठा-पटक ने व्यापक अनश्चितता पैदा की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जापान में भूकंप आया और, कुल मिलाकर, स्थिति निराशाजनक बनी रही।

2. हालांकि मेरा विश्वास है कि आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, न ही किसी के अपने देश में क्या घटित हो रहा है, इसके लिए कोई बहाना होना चाहिए, यदि हम विश्व की जमीनी हकीकत की अनदेखी करें तो हम भ्रम में रहेंगे। वैश्विक संकट ने

हमें प्रभावित किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, दो पूर्ववर्ती वर्षों के प्रत्येक वर्ष में 8.4 प्रतिशत की दर पर हुए विकास के बाद, 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यद्यपि हम अपनी अर्थव्यवस्था में इस मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने में सफल रहे हैं, तो भी इस वर्ष का निष्पादन निराशाजनक रहा है परन्तु यह भी एक सच्चाई है कि किन्हीं भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक विकास के मोर्चे पर अग्रणी देशों में बना हुआ है।

3. विगत दो वर्षों में अधिकांश समय हमें लगभग दो अंकों की समग्र मुद्रास्फीति से जूझना पड़ा। इस अवधि के दौरान हमारे मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपाय घरेलू मुद्रास्फीतिकारी दबावों को काबू करने की दिशा में केन्द्रित रहे। सख्त मौद्रिक नीति ने निवेश और उपभोग की वृद्धि पर प्रभाव डाला। राजकोषीय नीति में सब्सिडियों पर बढ़े हुए परिव्यय और उपभोक्ताओं पर ईंधन की ऊँची कीमतों का असर सीमित करने हेतु शुल्क में कटौतियाँ करनी पड़ीं। इसके परिणामस्वरूप विकास धीमा हुआ और राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई।

4. परन्तु मैं अच्छी बात भी बताना चाहूँगा, कृषि और सेवा क्षेत्र लगातार अच्छा कर रहे हैं, भारत के धीमे विकास का कारण लगभग पूरी तरह कमजोर औद्योगिक वृद्धि को माना जा सकता है। हालांकि हमारे पास 2011-12 की अंतिम तिमाही के सकल आंकड़े नहीं हैं, इस अवधि से सम्बंधित संकेतक यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार हो रहा है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली सेक्टरों में सुधार के लक्षण हैं। ये चुनिंदा अहम क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर प्रतीत होता है।

5. हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। हमें अपने वृहत आर्थिक माहौल में सुधार लाना है और मध्यावधि में उच्च विकास को बनाए रखने हेतु घरेलू विकास के कारकों को सुदृढ़ करना है। हमें सुधारों की गति में तेजी लानी होगी और अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष प्रबंधन में सुधार करना होगा।

6. हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस योजना का लक्ष्य “तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी विकास” है। यह योजना 2012-13 के बजट प्रस्तावों से आरंभ होगी। इसमें उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुरूप, मैंने पांच उद्देश्यों की पहचान की है जिन पर हमें आगामी वित्त वर्ष में कारगर ढंग से ध्यान देना चाहिए। ये हैं :—

- घरेलू मांग से अभिप्रेरित विकास पुनरुत्थान पर ध्यान केन्द्रित करना;
- निजी निवेश में उच्च वृद्धि के तीव्र पुनरुत्थान हेतु स्थितियाँ पैदा करना;
- कृषि, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों, विशेषकर कोयला, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नगर विमानन में आपूर्ति संबंधी बाधाओं पर ध्यान देना;
- विशेषकर कुपोषण की समस्या से अत्यधिक ग्रस्त 200 जिलों में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए निर्णायक उपाय करना; और
- वितरण प्रणालियों, गवर्नंस और पारदर्शिता में सुधार लाने; और काले धन तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे निर्णयों के समन्वित कार्यान्वयन में तेजी लाना।

7. आज भारत की ऐसी वैश्विक जिम्मेदारियाँ हैं जो पहले नहीं थी। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माताओं के उच्च स्तर पर हमारी मौजूदगी कुछ संतोष का विषय है। लेकिन इससे हमारे कंधों पर नई जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। यदि भारत अपनी आर्थिक मजबूती को बढ़ाना जारी रख सके तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता का स्रोत हो सकता है और डाँवाडोल वैश्विक पूँजी के लिए एक सुरक्षित गंतव्य मुहैया करा सकता है।

8. मैं जानता हूँ कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं। हमें इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अमल में लाने योग्य प्रस्तावों से युक्त एक विश्वसनीय कार्ययोजना की आवश्यकता है। ऐसा करने के अपने प्रयास में मुझे माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह का योग्य मार्गदर्शन और यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी के मजबूत समर्थन का लाभ मिला है।

अब मैं, अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त सिंहावलोकन से अपनी बात आरंभ करता हूँ।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

9. मैंने कल सदन के पटल पर वर्ष 2011-12 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले बारह महीनों में अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद

2011-12 में, वास्तविक अर्थों में 6.9 प्रतिशत पर बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि कृषि में 2.5 प्रतिशत, उद्योग में 3.9 प्रतिशत और सेवाओं में 9.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में, यह एक बड़ी गिरावट है, और मुख्यतया औद्योगिक वृद्धि, विशेषकर निजी निवेश में गिरावट के कारण है। ऋण की बढ़ती लागत और कमजोर घरेलू कारोबारी माहौल ने इस गिरावट में इजाफा किया।

10. समग्र मुद्रास्फीति वर्ष में अधिकांशतया ऊँची बनी रही। केवल दिसम्बर, 2011 में जाकर यह कुछ कम होकर 8.3 प्रतिशत तक आई और जनवरी, 2012 में 6.6 प्रतिशत रह गई। मासिक खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी, 2010 में 20.2 प्रतिशत थी जो कम होकर मार्च, 2011 में 9.4 प्रतिशत रह गई और जनवरी, 2012 में यह ऋणात्मक हो गई। यद्यपि फरवरी, 2012 की मुद्रास्फीति के आंकड़े मामूली रूप से बढ़े हैं, मुझे आशा है कि अगले कुछ महीनों में समग्र मुद्रास्फीति और कम होगी और उसके बाद स्थिर हो जाएगी।

11. भारत की मुद्रास्फीति मुख्यतया संरचनात्मक है। यह मुख्य रूप से कृषि संबंधी आपूर्ति की अड़चनों और वैश्विक लागतों में वृद्धि से प्रभावित होती है। इस बात के साक्ष्य हैं कि उच्च मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक अवधियों के सामान्य व्यवहार बन जाने की प्रवृत्ति होती है। सौभाग्यवश, खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु वितरण, भण्डारण और विपणन व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों ने हमें मुद्रास्फीति के अधिक कारगर प्रबंधन में सहायता की है और इससे खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

12. मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में भारत के वैदेशिक व्यापार का घटनाक्रम उत्साहवर्धक था। अप्रैल-जनवरी, 2011-12 के दौरान निर्यात में 23 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 243 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 391 बिलियन अमरीकी डालर के आयात में 29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। उत्साहजनक बात यह है कि भारत ने निर्यात और आयात बाजारों का सफलतापूर्वक विविधीकरण किया है। कुल व्यापार में आसियान सहित, एशिया की भागीदारी 2000-01 में 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 की पहली छमाही में 57.3 प्रतिशत हो गई है। इससे हमें यूरोप और कुछ सीमा तक संयुक्त राज्य अमरीका से उत्पन्न होने वाले वैश्विक संकट के प्रभाव का सामना करने में मदद मिली है।

13. 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता घाटा लगभग 3.6 प्रतिशत होने की संभावना है। इसने दूसरी और तीसरी तिमाहियों में कम हुए निवल पूँजी अन्तर्प्रवाहों सहित विनिमय दर पर प्रभाव डाला।

14. सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विहंगावलोकन से और कठिन वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं 2012-13 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.6 प्रतिशत +/- 0.25 प्रतिशत होने की आशा करता हूँ।

15. मुझे आशा है कि अगले वर्ष औसत मुद्रास्फीति कम रहेगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि घरेलू वित्तीय बचतों में सुधार के चलते चालू खाता घाटा अपेक्षाकृत कम रहेगा।

II. विकास

अब मैं विकास और राजकोषीय समेकन पर आता हूँ।

16. 2011-12 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में कम वसूलों तथा बढ़ी हुई सब्सिडियों के कारण हमारे राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई है। दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय हमारे अन्तर्निहित अनुमानों को बाद के घटनाक्रमों ने झुठला दिया। उच्च व्याज दरों और सामग्री की बढ़ती लागतों के कारण लाभ की गुंजाइश कम हो गई। इसने कारपोरेट करों में वृद्धि को प्रभावित किया। इसके अलावा, 90 अमरीकी डालर प्रति बैरल के अनुमानों की तुलना में 2011-12 में कच्चे तेल का औसत मूल्य 115 अमरीकी डालर से अधिक होने की संभावना है। इसने सब्सिडियों पर पूर्वानुमान से अधिक परिव्यय को आवश्यक बना दिया। वैश्विक माहौल में जारी अनिश्चितता ने हमारे लिए यह आवश्यक बना दिया है कि भविष्य में होने वाले झटकों का सामना करने हेतु पर्याप्त क्षमता सृजित करने के लिए राजकोषीय समेकन और बृहत आर्थिक आधारभूत तत्वों को मजबूत करने के बीच एक संतुलन बनाया जाए।

राजकोषीय समेकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम

17. केन्द्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम अधिनियम) और राज्य स्तर पर तदनुसूची अधिनियमों का कार्यान्वयन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व हमारे राजकोषीय शेष के सफल समेकन में अहम था। संयोगवश संकट का प्रादुर्भाव उस वर्ष हुआ जब 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को समाप्त करने के अधिदेशित लक्ष्यों को हासिल किया जाना था। उस समय राजकोषीय प्रोत्साहन देने के कारण सरकार को इन लक्ष्यों से हटना पड़ा। पिछले बजट भाषण में मेरी घोषणा के बाद, मैं, अब वित्त विधेयक, 2012 के भाग के रूप में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुरःस्थापित कर रहा हूँ।

व्यय सुधार

18. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत केन्द्र के राजकोषीय लक्ष्य बजट दस्तावेजों में दिए गए हैं। इस बीच, मैं इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो व्यय सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले कदम हैं। पहला, राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने हेतु पिछले बजट में शुरू की गई प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को एक राजकोषीय मानदंड के रूप में लाया जा रहा है। प्रभावी राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बीच अंतर है। इस पर ध्यान केन्द्रित करने से राजस्व घाटे के उपभोग संबंधी घटक में कमी लाने और अभिवृद्धित पूंजीगत व्यय हेतु क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी।

19. दूसरा, इस अधिनियम में "मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण" के लिए प्रावधान किया जा रहा है। यह विवरण व्यय संकेतकों के लिए तीन वार्षिक चल लक्ष्य निर्धारित करेगा। यह प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं हेतु संसाधनों के आवंटन के लिए नए सिरे से कार्रवाई करने और अपनी उपयोगिता खो चुकी अन्य योजनाओं को बन्द करने में सहायक होगा। इससे बहुवर्षीय बजटिंग फ्रेमवर्क में अधिक निश्चितता आएगी और व्यय प्रबंध में कार्यकुशलता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

20. बारहवीं योजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल एवं कारगर बनाने तथा उनकी संख्या घटाने और आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निधियों की बेहतर पकड़ तथा उपयोग को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय आयोजना स्कौन मॉनिटरिंग प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

सब्सिडी

21. राजकोषीय समेकन में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ाने तथा व्यय में कमी लाने संबंधी दोनों प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हमें अपने राजस्व व्यय, विशेष रूप से सब्सिडियों में हुई बढ़ोतरी पर व्यापक रूप से ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियों में खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडियां शामिल हैं। इस स्थिति पर हमारे विकास में प्रदान की जाने वाली कुछ सब्सिडियां अपरिहार्य हैं। लेकिन जब वे अर्थव्यवस्था में वृहद् आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करती हैं और इससे भी आगे जब वे आशयित लाभग्राहियों तक नहीं पहुंचती तो अवांछनीय हो जाती हैं।

22. सरकार ने निर्णय लिया है कि 2012-13 से खाद्य से सम्बद्ध सब्सिडियां और खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अन्य सभी सब्सिडियों को उस सीमा तक वित्तपोषित किया जाएगा जहां तक कि वे अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बनी रह सकें। मेरा प्रयास होगा कि 2012-13 में केन्द्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे रखा जाए। आगामी तीन वर्षों में इसे पुनः घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75 प्रतिशत पर लाया जाएगा। सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसा उपाय करना आवश्यक है। हमारा प्रयास अब सब्सिडियों की बेहतर लक्षित प्रणाली और दोषरहित सुपुर्दगी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने पर होगा।

23. श्री नन्दन नीलेकणि की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए आईटी नीति के सम्बन्ध में कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबन्ध प्रणाली (एमएफएमएस) तैयार की गई है ताकि विनिर्माणकर्ता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों की आवाजाही तथा सब्सिडियों पर बराबर नजर रखी जा सके। इसे 2012 के दौरान सम्पूर्ण देश में लागू किया जाएगा। खुदरा व्यापारी और अन्त में किसानों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अन्तरण अनुवर्ती चरणों में किया जाएगा। उर्वरकों के दुरुपयोग में कमी लाकर सब्सिडियों पर व्यय को कम करने के इस उपाय से 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

24. सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तीन तेल विपणन कम्पनियों ने ग्राहक सेवा में सुधार करने तथा रिसाव कम करने हेतु एलपीजी पारदर्शिता पोर्टल्स की शुरुआत की है। बाजार मूल्य पर एलपीजी के क्रय तथा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सीधे लाभग्राही के बैंक खाते में करने की एक प्रायोगिक परियोजना मैसूर में शुरू की गई है। किरोसीन पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण को लाभग्राही के बैंक खाते में करने की ऐसी ही एक प्रायोगिक परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में प्रारंभ

की गयी है। झारखण्ड राज्य में आधार प्लेटफार्म को भी पीडीएस राशन कार्डों की वैधता हेतु सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है।

25. इन प्रायोगिक परियोजनाओं से यह परिलक्षित होता है कि सब्सिडी व्यय में पर्याप्त किफायती 'आधार' प्लेटफार्म के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास होगा कि इन 'आधार' समर्थित भुगतानों में आगामी छह महीनों के भीतर कम से कम 50 चुनिंदा जिलों में अनेक सरकारी योजनाओं हेतु और तेजी लाई जाए।

कर सुधार

26. जैसाकि माननीय सदस्यों की ज्ञात है, प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक अगस्त, 2010 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था। हमारी यह पूरी इच्छा थी कि इस प्रत्यक्ष कर संहिता को 01 अप्रैल, 2012 से लागू किया जाए। तथापि, हमें 9 मार्च, 2012 को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हम इस रिपोर्ट की शीघ्र जांच करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

27. इसी प्रकार, संविधान संशोधन विधेयक, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक प्रारम्भिक उपाय है, मार्च 2011 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था और यह संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है। चूंकि हमें इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है, केन्द्र तथा राज्य के वस्तु एवं सेवा कर हेतु मॉडल विधान का मसौदा तैयार करने का कार्य राज्यों के साथ परामर्श करते हुए प्रगति पर है।

28. राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की संरचना को अनुमोदित कर दिया गया है। यह नेटवर्क एक राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा और अगस्त 2012 तक काम करना शुरू कर देगा। जीएसटीएन सभी राज्यों के लिए साझेदारी आधार पर समान पैन-आधारित पंजीकरण विवरणियां दर्ज करना और भुगतान प्रोसेसिंग को कार्यान्वित करेगा। पैन का उपयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए समान पहचानकर्ता रूप में किया जाएगा जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा तथा कर अपवंचन को रोकेंगे। मैं सभी सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन ऐतिहासिक विधानों के शीघ्र पारित किए जाने हेतु समर्थन दें।

विनिवेश नीति

29. सरकार ने सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के विनिवेश सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण को पुनः व्यक्त किया है। इन उद्यमों को निजी क्षेत्र की तुलना में वापसी खरीदों तथा स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध जैसी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में एक समान भूमिका दी जा रही है। सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के लिए राजकोष प्रबन्ध विकल्प भी बढ़ाए गए हैं। इससे सभी पण्यधारियों हेतु मूल्य तथा संसाधनों के प्रकटीकरण के अलावा, सरकारी आस्तियों से सम्बद्ध प्रतिलाभों में सुधार तथा विनिवेश प्रक्रिया के लिए पारदर्शी माहौल का समर्थन करने में सहायता मिलेगी।

30. 2011-12 में, ₹ 40,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में, सरकार विनिवेश से लगभग ₹ 14,000 करोड़ जुटाएगी। 2012-13 में, विनिवेश के माध्यम से ₹ 30,000 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं यह दोहराना चाहूंगा कि जहां हम सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के स्वामित्व में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं, वहीं इनमें कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व तथा प्रबन्ध नियंत्रण सरकार के पास होगा।

निवेश माहौल में मजबूती लाना

31. घरेलू निवेश माहौल विगत वर्ष कई कारणों से प्रभावित रहा। समय की मांग है कि नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जाएं और बड़ी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

32. संगठित रिटेल, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों को लाभान्वित करते हुए, भारी किफायत की वजह से मध्यस्थ लागत को घटाने में मदद करता है। वर्तमान में, एफडीआई की अनुमति सिंगल ब्रांड तथा 'नकद दो और माल लो' थोक व्यापार में 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध है। विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना करने पर मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान करने का निर्णय आस्थगित रखा गया है। राज्य सरकारों से परामर्श करके एक व्यापक सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार

33. विस्तारित सीमा-पार उत्पादन श्रृंखलाओं तथा एक ही समूह की इकाइयों के भीतर बढ़ते व्यापार के साथ वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार कर-मुकदमेबाजी में भारी कमी ला सकता है और विदेशी निवेशकों को कर निश्चितता की व्यवस्था प्रदान कर सकता है। यद्यपि अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार के प्रावधान को प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में शामिल किया गया है, मैं वित्त विधेयक, 2012 में इसको लाकर इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय क्षेत्र

34. बचतकर्ताओं तथा निवेशकों के बीच अधिक सक्षम बाजार मध्यस्थता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए हैं।

35. वित्तीय लिखतों में निर्बाध बचतों को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू पूंजी बाजार की संरचना में सुधार करने हेतु, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना नामक एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। यह योजना ऐसे नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत की आयकर कटौती की अनुमति प्रदान करेगी जो सीधे ₹ 50,000 इक्विटियों में निवेश करते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय ₹ 10 लाख से कम है। इस योजना की समयबंदी (लॉक-इन पीरियड) 3 वर्ष होगी। योजना का ब्यौरा यथासमय घोषित किया जाएगा।

पूँजी बाजार

36. वर्ष 2011-12 के दौरान, हमने पूंजी बाजार को व्यापक रूप देने तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। किए गए उपायों में दीर्घकालिक आधारभूत संरचना बांडों, कारपोरेट बांडों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है। विदेशी वाणिज्यिक

उधार (ईसीबी) संबंधी सीमा भी बढ़ायी गयी है तथा अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों को विनिर्दिष्ट भारतीय म्यूचुअल फंडों तथा सीधे इक्विटियों में निवेश की अनुमति भी दी गयी थी।

37. मैं, अब पूंजी बाजार में सुधारों को और तीव्र करने हेतु निम्न आगामी उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

- अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को भारतीय कारपोरेट बांड बाजार में पहुंच की अनुमति प्रदान करना;
- प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, उनकी लागत कम करना तथा कम्पनियों को छोटे कस्बों में अधिक खुदरा निवेशकों तक पहुंच बनाने में मदद करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मौजूदा आईपीओ प्रक्रिया के अलावा, मैं, कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव करता हूँ कि वे स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में ₹10 करोड़ तथा अधिक की राशि के आईपीओ जारी करें;
- शेयरधारक की वोटिंग सम्बन्धी मौजूदा प्रक्रिया के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के जरिए कम्पनियों के महत्वपूर्ण निर्णयों में शेयरधारक की व्यापक भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना, जिसे प्रारम्भ में शीर्ष सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा; और
- उच्चतम सीमा के अधीन भारतीय पूंजी बाजार में अपेक्षाकृत अधिक विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति में दो तरफा समरूपता की अनुमति देना।

विधायी सुधार

38. हमें "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011", "बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" तथा "बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2008" के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं। इन विधेयकों के सम्बन्ध में सरकारी संशोधनों को संसद के इस सत्र में लाया जाएगा।

39. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए, सरकार संसद के बजट सत्र में निम्नलिखित विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है :

- सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012;
- राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;

- भारतीय स्टॉप (संशोधन) विधेयक, 2012; और
- भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अधिकरण विधेयक, 2012।

40. प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली विधि प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

बैंकों और वित्तीय स्वामित्व वाली कम्पनियों का पूंजीकरण

41. सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा संरक्षित करने के प्रति कृतसंकल्प है। वर्ष 2012-13 के लिए, मैं नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए ₹ 15,888 करोड़ मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार वित्तीय स्वामित्व वाली एक कंपनी बनाए जाने की संभावना भी तलाश कर रही है। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी।

42. बैंक भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए, एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जो 2012-13 में कार्यान्वित की जाएगी। पूंजीकरण प्रक्रिया में दुविधा तथा दोहराव से बचने और आंकड़ों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से, 2012-13 में एक केन्द्रीय अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) निक्षेपागार स्कीम तैयार की जाएगी।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

43. मौजूदा वर्गीकरण की दुबारा जांच करने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सम्बन्धित स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी कर दिया जाएगा।

वित्तीय समावेशन

44. वर्ष 2010-11 में, 2000 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों में बिजनेस सम्पर्कियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए "स्वाभिमान" अभियान शुरू किया गया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मार्च, 2012 तक समाविष्ट की जाने वाली 73,000 हजार अभिज्ञात बस्तियों में से, लगभग 70,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं। इसके साथ ही, 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। शेष बस्तियों को भी 31 मार्च, 2012 तक समाविष्ट किए जाने की संभावना है। अगले कदम के तौर पर, इन इलाकों में बहुत छोटी-छोटी (अल्ट्रा स्मॉल) शाखाएं खोली जा रही हैं। यहां बिजनेस सम्पर्कों नकद लेन-देन करेंगे।

45. वर्ष 2012-13 में, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के 1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में तथा जनगणना 2011 के अनुसार 2,000 से अधिक की आबादी वाली अन्य बस्तियों में "स्वाभिमान" अभियान चलाने का प्रस्ताव करता हूँ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

46. ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे यह जताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 81 ने सफलतापूर्वक स्वयं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में बदल लिया है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड अन्तरण प्रणाली को अपना चुके हैं।

47. सरकार ने वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है और फरवरी, 2012 के अन्त तक इनमें से 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम पूरा हो चुका है। मैं कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण स्कीम को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सभी राज्य इसमें अपना योगदान कर सकें।

III. अवसंरचना और औद्योगिक विकास

मैं अब अवसंरचना और औद्योगिक विकास की ओर आता हूँ।

48. पर्याप्त अवसंरचना का अभाव हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इस संबंध में अभी तक हमारे द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में सरकारी निवेश और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के सुमेल से अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना रहा है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान, अवसंरचना निवेश बढ़कर ₹ 50 लाख करोड़ तक हो जाएगा। आशा है कि इसकी आधी राशि निजी क्षेत्र से आएगी।

49. अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता योजना के अन्तर्गत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ), इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की दशा में एक महत्वपूर्ण लिखत है। इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई (बांध, चैनलों और तटबंधों) टर्मिनल बाजारों, कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना, मुदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को इस स्कीम के अन्तर्गत वीजीएफ के लिए पात्र बनाया जाए। तेल एवं गैस/एलएनजी भण्डार सुविधाओं तथा तेल एवं गैस पाइपलाइनों, दूर संचार के लिए स्थायी नेटवर्क और दूर-संचार टावरों को भी वीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र बनाया जाएगा।

50. सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी मोड में रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम की कंपनी स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त आत्मनिर्भरता हासिल करने और अति आधुनिक रक्षा सामग्री उत्पादन का दोहरा प्रयोजन सिद्ध होगा।

51. दीर्घ स्वरूप की पेंशनों तथा बीमा निधियों के लिए विदेशी बाजार के सीधे दोहन के लिए मैंने अवसंरचना बाण्ड निधियों के गठन की घोषणा की थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ₹ 8000 करोड़ की प्रारंभिक राशि से पहली अवसंरचना ऋण निधि इस माह के आरम्भ में शुरू की गयी है।

52. वर्ष 2011-12 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹ 30,000 करोड़ के करमुक्त बांडों की घोषणा की गयी थी। मैं, 2012-13 में इसे बढ़ाकर ₹ 60,000 करोड़ करने

का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें एनएचआई के लिए ₹ 10,000 करोड़, आईआरएफसी के लिए ₹ 10,000 करोड़ आईआईएफसीएल के लिए ₹ 10,000 करोड़, हुडको के लिए ₹ 5,000 करोड़, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ₹ 5,000 करोड़ सिडबी के लिए ₹ 5,000 करोड़ पत्तनों के लिए ₹ 5,000 करोड़, और विद्युत के लिए ₹ 10,000 करोड़ शामिल हैं।

53. अवसंरचना क्षेत्रों की एक सुमेलित मास्टर सूची सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इससे नीतिगत तथा विनियामक व्यवस्थापन में अस्पष्टता दूर करने और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

54. अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण मिलने में सुविधा के लिए, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने ऋण बढ़ाने और इससे वित्त प्राप्त करने के लिए एक संरचना बनायी है। सीधे ऋण लेने तथा विकास-कर्ताओं के सैद्धान्तिक अनुमोदन की स्वीकृति के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं हेतु निविदाएं आमंत्रित करने से पहले, एक सहायता संघ भी बनाया गया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

55. सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना, और 10 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। यह नीति पूरे देश में राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण अंचलों (एनआईएमजेड) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

56. अब मैं, कुछ ऐसे विषयों पर आता हूँ जिन्होंने पिछले महीनों के अवसंरचना और औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।

विद्युत तथा कोयला

57. विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, ईंधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पादन की संभावनाओं को धूमिल कर रही हैं। इससे मुक्ति के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को परामर्श दिया गया है कि वह उन विद्युत संयंत्रों, जिन्होंने डिसकॉम के साथ दीर्घकालिक पावर परचेज करार निष्पादित कर लिए हैं और जो 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व चालू हो जाएंगे, के साथ ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर करें। आबंटित कोयला खानों की आवधिक समीक्षा तथा आवश्यक होने पर वि-आबंटन (डी-अलोकेशन) पर सिफारिशें देने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी दल की स्थापना की जा रही है।

58. मैं मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के अंश निधियन रूपया ऋणों को विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

परिवहन : सड़क तथा नागर विमानन

59. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचडीपी के अन्तर्गत 2011-12 में 7,300 कि.मी. लम्बाई को कवर करते हुए

परियोजनाएं देने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना नियत किया है। यह 2010-11 में अभी तक प्रदत्त सर्वाधिक लम्बाई 5,082 कि.मी. से 44 प्रतिशत ज्यादा है। 2011-12 के दौरान प्रदत्त 44 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाओं ने प्रीमियम आकृष्ट किया है। मैं, अगले वर्ष एनएचडीपी के तहत 8,800 कि.मी. लम्बाई कवर करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2012-13 में इस मंत्रालय का आवंटन 14 प्रतिशत बढ़ाते हुए ₹ 25,360 करोड़ कर दिया गया है।

60. सड़क निर्माण परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, सड़कों तथा राजमार्गों, बशर्ते कि वे मूल परियोजनाओं का भाग हों, के लिए पथ-कर प्रणाली को संचालित करने व इसके रख-रखाव पर पूंजीगत व्यय के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

61. एयरलाइन उद्योग वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस क्षेत्र की उच्च प्रचालन लागत मुख्यतया एवियेशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के ऊंचे दाम के कारण है। एटीएफ की लागत घटाने के लिए, सरकार ने भारतीय वाहकों को वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की तरह सीधे एटीएल आयात करने की अनुमति दे दी है।

62. नागर विमानन क्षेत्र के तात्कालिक वित्तीय सरकारों के निवारण के लिए, मैं। बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल सीमा के अधीन रहते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए एयरलाइन उद्योगों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

63. अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन में कार्यरत किसी हवाई परिवहन उपक्रम की इक्विटी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी हेतु विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर

64. पश्चिम समर्पित रेल दुलाई कॉरिडोर के साथ-साथ इसके दोनों ओर दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है। सितम्बर 2011 में, 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 18,500 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने डीएमआईसी परियोजना में जापानी सहायता के रूप में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की है।

आवास क्षेत्र

65. महानगरी और कस्बों में रहने वाले निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास की कमी को देखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :

- कम लागत वाली किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना;

- आवासीय ऋणों के लिए संस्थागत ऋण की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि की स्थापना;
- ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान को ₹ 3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4,000 करोड़ करना;
- ₹ 15 लाख तक के आवास ऋण पर। प्रतिशत की व्याज सहायता योजना का एक और वर्ष के लिए विस्तार करना, जहां मकान की लागत ₹ 25 लाख से अधिक न हो; और
- प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष वित्त की सीमा को ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख करना।

उर्वरक

66. यूरिया में भारत की आयात-निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने यूरिया के लिए मूल्य-निर्धारण और निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने हेतु कदम उठाए हैं। आशा है कि इस निवेश नीति के कार्यान्वयन से, देश अगले पाँच वर्षों में यूरिया के विनिर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पोटैसिक-फॉस्फेटिक (पी एंड के) उर्वरक के मामले में, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के प्रयोग को बेहतर विस्तार कार्य के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। यह उर्वरक पूरी तरह देश में विनिर्मित होता है। वर्धित उत्पादन से पोटैसिक-फॉस्फेटिक क्षेत्र में किए जाने वाले आयातों पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी।

वस्त्र

67. सरकार ने, हाल ही में, हथकरघा बुनकरों और उनकी सरकारी समितियों के ऋणों की भाफी के लिए ₹ 3,884 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है।

68. मैं अब, पहले से क्रियाशील 4 मेगा हथकरघा क्लस्टरों के अलावा, दो और मेगा क्लस्टरों की घोषणा करता हूँ जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटुर जिलों को कवर करेगा और दूसरा झारखंड के गोड्डा और पड़ोसी जिलों को। मैं हथकरघा, विद्युत-करघा और चर्म क्षेत्रों के 5 मेगा क्लस्टरों की महिला कामगारों के लिए शयनागारों (डॉर्मिटोरियों) की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

69. गरीब हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वस्त्र मंत्रालय देश के अनेक भागों में बुनकर सेवा केन्द्रों का संचालन करता है। मैं मिजोरम, नागालैंड और झारखंड में एक-एक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, बारहवीं योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्स्टाइल्स के संवर्धन और प्रयोग हेतु ₹ 500 करोड़ की प्रायोगिक योजना की घोषणा करता हूँ।

70. स्थानीय दस्तकारों और बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मैं महाराष्ट्र के इचलकरन्जी में ₹ 70 करोड़ के बजट आवंटन से एक विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

71. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं सिडबी के साथ ₹ 5000 करोड़ के इंडिया ऑपरच्युनिटीज वेंचर फंड की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ।

72. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं। वे पूँजी जुटाने के लिए मुख्यतया बैंकों और अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋणों पर निर्भर करते हैं। इन उद्यमों के लिए वित्त की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में मुम्बई में दो लघु एवं मध्यम उद्यम एक्सचेंजों की शुरुआत की गई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सरकारी अधिप्राप्ति नीति

73. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बाजार पहुँच के संवर्धन के उद्देश्य से, सरकार ने एक नीति को अनुमोदित किया है जिसके तहत मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत भाग इन उद्यमों से क्रय करना अपेक्षित है। इसमें से, 4 प्रतिशत भाग अनु. जाति/जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित किया जाएगा।

IV. कृषि

मैं अब कृषि पर आता हूँ।

74. कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहेगा। कृषि और सहकारिता विभाग के कुल आयोजना परिव्यय में 2011-12 के ₹ 17,123 करोड़ से 18 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 2012-13 में ₹ 20,208 करोड़ किया जा रहा है।

75. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु परिव्यय को 2011-12 के ₹ 7860 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 9217 करोड़ किया जा रहा है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के कार्यक्रम से धान के उत्पादन और उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। पूर्वी भारत के राज्यों ने खरीफ 2011 में सात मिलियन टन के अतिरिक्त धान की उत्पादन की सूचना दी है। मैं इस योजना के लिए 2011-12 के ₹ 400 करोड़ के आवंटन को बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 1000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

76. इस वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, मैं विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम को ₹ 300 करोड़ के आवंटन का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित सिंचाई के तहत और अधिक कृषि क्षेत्रों को लाना है।

77. सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शेष कार्यकलापों का कुछ मिशन में विलय करना चाहती है। ये मिशन निम्नलिखित हैं :—

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य धान, गेहूँ, दलहन, ज्वार-बाजरा आदि और चारे के संबंध में उपज के अंतर को पाटना है। चल रहे एकीकृत दलहन ग्राम विकास, पोषक अनाजों का संवर्धन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम अब इस मिशन का भाग बन जाएंगे;

- (ii) अति लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में शुरू किया जा रहा है। वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इस मिशन के साथ मिला दिया जाएगा;

- (iii) राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन और पाम तेल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है;

- (iv) राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य कृषि कार्य में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हेतु किसानों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देना है; और

- (v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी में विविधता लाना है। इसमें केसर संबंधी कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक आहार मिशन

78. प्रोटीन पूरक आहार मिशन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, विश्व बैंक की सहायता से ₹ 2,242 करोड़ की परियोजना शुरू की जा रही है। फ़ेश वाटर अक्वाकल्चर के अलावा, मछली उत्पादन का दायरा समुद्र तटीय अक्वाकल्चर तक बढ़ाने के उद्देश्य से, 2012-13 में परिव्यय को बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ किया जा रहा है। कुक्कुटपालन, सूरअपालन और बकरीपालन के लिए भी उपयुक्त आवंटन किए जा रहे हैं।

कृषि ऋण

79. किसानों को समय पर सस्ते ऋण की आवश्यकता होती है। मैं 2012-13 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर ₹ 5,75,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह वर्तमान वर्ष के लक्ष्य की तुलना में ₹ 1,00,000 करोड़ अधिक है।

80. किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज सहायता योजना 2012-13 में जारी रहेगी। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, प्रक्राम्य भाण्डागार रसीद प्रस्तुत करने पर 6 माह तक फसल-पश्च ऋणों पर भी समान ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इससे किसानों को अपनी उपज भाण्डागारों में रखने हेतु बढ़ावा मिलेगा।

81. छोटे और सीमान्त किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों के सवितरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अल्पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित्त निधि की स्थापना की जा रही है। मैं, इस निधि के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तपोषण हेतु नाबार्ड को ₹ 10,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

82. किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एक प्रभावी लिखत है। केसीसी एक स्मार्ट कार्ड बने उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधित की जाएगी जिससे कि इसका उपयोग एटीएम पर किया जा सके।

कृषि अनुसंधान

83. आने वाले दशकों में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, उत्पादकता बढ़ाने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजों पर निर्भर करेगा। हमें पौध और बीज की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जिनसे उपज अधिक हो और इनमें जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध क्षमता हो। मैं, ऐसी वैज्ञानिक खोजों के लिए संस्था और अनुसंधान दल दोनों के लिए पुरस्कारों के रूप में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 200 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सिंचाई

84. जब तक हम जल को एक संसाधन के रूप में नहीं मानते, तो वह दिन दूर नहीं जब जल की कमी से हमारे कृषि उत्पादन को खतरा महसूस होने लगेगा। वर्षा जल संचय योजना का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढाँचात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं। एआईबीपी हेतु आबंटन 2012-13 में 13 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 14,242 करोड़ किया जा रहा है।

85. सिंचाई परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु प्रचुर संसाधन जुटाने के लिए, सरकारी स्वामित्व वाली सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी क्रियाशील की जा रही है। यह कंपनी सूक्ष्म-सिंचाई, ठेके पर खेतीबाड़ी, अपजल प्रबंधन और स्वच्छता जैसे उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण पर केंद्रित रहते हुए 2012-13 में अपना कार्य आरंभ कर देगी।

86. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा ₹ 439 करोड़ की लागत से मुर्शिदाबाद जिले के कंडी उप-मंडल के लिए बाढ़ प्रबंधन की एक परियोजना अनुमोदित की गई है जिसे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निधिपोषण किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

87. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विगत 5 वर्ष से 8 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से बढ़ रहा है। बेहतर आऊटरीच और स्थानीय जरूरतों के माफिक अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए, 2012-13 में राज्य सरकारों के सहयोग से "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

88. सरकार ने देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित करने के उपाय किए हैं। आधुनिक साइलो के रूप में 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता के सृजन को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 मिलियन टन क्षमता सृजित की जा रही है, जिसमें से 3 मिलियन टन भंडारण क्षमता 2011-12 के अंत तक जुड़ जाएगी और 5 मिलियन टन अगले वर्ष जोड़ी जाएगी।

862 GI/12-3

V. समावेशन

मैं अब समावेशी विकास संबंधी प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहूँगा।

अनुसूचित जाति और जनजातीय उप-आयोजनाएं

89. वर्ष 2011-12 से, आयोजना आबंटनों के भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप परियोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप आयोजनाओं (टीएसपी) हेतु अलग-अलग लघु शीर्षों के अंतर्गत आबंटन किए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में, एससीएसपी के लिए किया गया आबंटन ₹ 37,113 करोड़ है जो 2011-12 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में टीएसपी हेतु आबंटन ₹ 21,710 करोड़ है जो 2011-12 से 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खाद्य सुरक्षा

90. हमारी सरकार ने सभी लक्षित लोगों, विशेषकर गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए खाद्य को एक कानूनी हक बनाते हुए परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सृजित करने के निश्चित उपाय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है।

91. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किए जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए, आधार मंच का प्रयोग करते हुए, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र सृजित किया जा रहा है। यह दिसम्बर, 2012 तक लागू हो जाएगा।

बहु-क्षेत्रीय पोषण संवर्धन कार्यक्रम

92. भारत की पोषाहार चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय परिषद् में किए गए निर्णय के अनुसरण में, चुनिंदा 200 उच्च समस्याग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण से निदान हेतु एक बहु क्षेत्रीय कार्यक्रम 2012-13 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। यह पोषाहार, स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण योजनाओं में सहयोग करेगा।

93. इस संदर्भ में, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना को सुदृढ़ और नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए, वर्ष 2011-12 में ₹ 10,000 करोड़ की तुलना में, 2012-13 के लिए ₹ 15,850 करोड़ का आबंटन किया गया है। यह वृद्धि 58 प्रतिशत से अधिक बैठती है।

94. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम ने विद्यालयों में नाम लिखवाने, पढ़ाई जारी रखने व उपस्थिति को बढ़ाया है और बच्चों में पोषण स्तरों को सुधारने में भी सहायता की है। मैं, 2011-12 में ₹ 10,380 करोड़ की तुलना में 2012-13 में इस स्कीम के लिए ₹ 11,937 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

95. 11 से 18 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों के विकास के लिए पोषण संबंधी जरूरतों के समाधान और शैक्षिक व कौशल विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, राजीव गांधी किशोरार स्तर सशक्तीकरण स्कीम 'सबला' पिछले वर्ष शुरू की गई है। 2012-13, में, इस स्कीम के लिए ₹ 750 करोड़ का आबंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

96. पानी की गुणवत्ता के साथ-साथ अपर्याप्त स्वच्छता कुपोषण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैं, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु बजटीय आबंटन 2011-12 में ₹ 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 14,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

97. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक सफल कार्यक्रम रहा है। मैं 2012-13 में, ₹ 24,000 करोड़ उपलब्ध कराते हुए इस योजना के आबंटन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राज्यों में कनेक्टिविटी कार्य में तीव्रता आएगी।

98. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के माध्यम से देश भर में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम पंचायत क्षमता निर्माण हेतु विद्यमान योजनाओं का विस्तार करेगा।

99. अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में, मैंने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया था। हमने 2011-12 के बजट अनुमान में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करके 2012-13 में ₹ 12,040 करोड़ के वर्धित आबंटन से बारहवीं योजना में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम का कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य घटक शामिल है जो, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में विकास की गति को द्रवी करने के लिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कालाहांडी-बोलागीर-कोरापुट क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रभाव कम करने की विकास परियोजनाएं और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कवर करेगी।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

100. मैं, इस वर्ष, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर ₹ 20,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, देश में भांडागारण को कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत विशेष तौर पर भांडागारण सुविधाएं सृजित करने के लिए उपर्युक्त आबंटन में से ₹ 5,000 करोड़ की राशि अलग से निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षा

101. शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अप्रैल, 2010 से सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैंने शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 25,555 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। यह 2011-12 की तुलना में 21.7 प्रतिशत अधिक है।

102. बारहवीं योजना में, उत्कृष्टता प्रतीक के तौर पर मैंने मॉडल स्कूलों के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इनमें से, 2500 स्कूलों की स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत की जाएगी।

103. गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए, मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। मैंने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 2012-13 में ₹ 3,124 करोड़ आवंटित किए हैं जो 2011-12 में किए गए आवंटन से लगभग 29 प्रतिशत अधिक है।

104. बैंकों द्वारा एक शिक्षा ऋणों योजना क्रियावित की जा रही है। सुपात्र विद्यार्थियों को ऋण निर्बाध रूप से मिलना सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस प्रयोजनार्थ एक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य

105. कहते हैं कि अनवरत प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि पिछले एक वर्ष में पोलियो के एक भी नए मामले की सूचना नहीं थी। विद्यमान यूनियनों को आधुनिकीकृत बनाकर और चेनई के पास एक नई एकीकृत टीका यूनिट की स्थापना करके, सरकार टीका सुरक्षा प्राप्त करेगी और रोग उन्मूलन एवं निवारण पर अनवरत दबाव बनाएगी।

106. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता-‘आशा’ के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आयोडीन कमी संबंधी गड़बड़ियों से बचाव, 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण और बच्चों के जन्म के बीच बेहतर अंतराल सुनिश्चित करने जैसे दायित्वों को शामिल करते हुए आशा-कार्यकलापों का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। समुदाय स्तर पर, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के साथ ही कुपोषण संबंधी कार्यक्रम की सहायता करने के लिए संयोजक के रूप में ‘आशा’ के लिए अधिक सक्रिय भूमिका की परिकल्पना की गई है। चूंकि ‘आशा’ को कार्यक्रम-वार, निष्पादन आधारित भुगतान मिलते हैं, इससे उनका मेहताना भी बढ़ जाएगा। मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2011-12 में किए गए ₹ 18,115 करोड़ के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 20,822 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. शहरी क्षेत्रों में लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना और विद्यमान सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन करना है। इस योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि 7 और सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन को इसमें कवर किया जा सके। यह, किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्कीम की सुलभता को बढ़ाएगा।

रोजगार और कौशल विकास

108. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का आजीविका सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहली बार, ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रभावशाली न्यूनतम मजदूरी की कोई दर बनी है। दुःखद प्रवासन अब कम हुआ है। सामुदायिक आस्तियां सृजित की गई हैं। बंजर और परती भूमि की उत्पादकता बढ़ी है। आस्तियां की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत और मनरेगा के बीच व्यापक सहयोग-समन्वय कायम करते हुए कृषि व संबद्ध ग्रामीण आजीविकाओं पर जोर दिया जा रहा है।

109. स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए, स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में नए सिरे से तैयार किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत, एक उप घटक, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना महिला किसानों को बेहतर ढंग से लक्षित करते हुए, उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। मैं, इस मिशन के लिए आबंटन 2011-12 में किए गए ₹ 2,914 करोड़ से 34 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 3,915 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. पिछले वर्ष के बजट में, मैंने "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" के सृजन की घोषणा की थी। इसे नाबार्ड में स्थापित कर दिया गया है। 2012-13 में ₹ 200 करोड़ उपलब्ध कराते हुए, मैं इस निधि को बढ़ाकर ₹ 300 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह निधि आजीविका अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों को भी सहायता देगी। यह, महिला स्व-सहायता समूहों की बैंक ऋणों तक पहुंच को बढ़ाते हुए उनका सशक्तीकरण करेगी। मैं, महिला स्व-सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹ 3 लाख तक के ऋण के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। वे महिला स्व-सहायता समूह, जो समय पर ऋण की अदायगी करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे प्रभावी दर घटकर 4 प्रतिशत रह जाएगी। यह कार्यक्रम, पहले चरण में वामपंथी अतिवाद ग्रस्त जिलों सहित 150 जिलों के चुनिंदा 600 ब्लॉकों पर ध्यान देगा।

111. यह प्रस्ताव है कि आजीविका के माध्यम से लिक्विडिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। यह फाउंडेशन, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 170 जिलों को कवर करते हुए सिविल सोसाइटी के कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों में सहायता करेगा और उनका विस्तार करेगा। निजी न्यासों और परोपकारी संगठनों को स्वायत्त निकाय के साथ भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ऐसे विकास की व्यवस्था व्यवसायिक रूप से की जा सके।

112. सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक ऋण संबद्ध एक सब्सिडी कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु आबंटन 2011-12 में किए गए ₹ 1,037 करोड़ से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 2012-13 में, ₹ 1,276 करोड़ किया गया है।

कौशल विकास

113. वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 26 नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया, इस प्रकार 2009 से मंजूर की गई योजनाओं की संख्या दोगुनी होकर 52 हो गयी। इनकी कुल वित्तपोषण वचनबद्धता ₹ 1,205 करोड़ है। आशा है कि 10 वर्षों की समाप्ति पर, इन परियोजनाओं से 6.2 करोड़ व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाएंगे और निजी क्षेत्र में प्रति वर्ष 1.25 करोड़ व्यक्तियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता बढ़ेगी।

114. एनएसडीसी के भागीदारों ने 24 राज्यों के 220 जिलों में 496 स्थायी और 2429 चल केन्द्र खोले हैं। 89,500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिला है। एनएसडीएफ के तहत 10 क्षेत्रीय कौशल परिषदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से ऑटोमोबिल, सुरक्षा और खुदरा क्षेत्रों की 3 कौशल परिषदों ने कार्य शुरू कर दिया है। वर्ष 2012-13 हेतु मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को ₹ 1000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

115. कौशल विकास हेतु संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए, मैं पृथक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे युवाओं को बाजारोन्मुख कौशल अर्जित करने में फायदा होगा।

116. जम्मू-कश्मीर में 2011-12 से "हिमायत" नामक नई योजना की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम की पूरी लागत केन्द्र द्वारा वहन की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर तबकों की जरूरतें

117. मैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आबंटन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 2011-12 में ₹ 6,158 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 8,447 करोड़ कर रहा हूँ। क्रियान्वित की जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 की जा रही है।

118. बीपीएल परिवार के प्रमुख रोजी कमाने वाले 18 से 64 आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत इस समय ₹ 10,000 की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। मैं यह राशि दोगुनी करके ₹ 20,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी का योगदान मुहैया कराने की आशा करता हूँ।

119. पेंशन की मद में स्पैच्छिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 2010 में 'स्वावलंबन' नामक सह-अंशदायी योजना शुरू की गई थी। फरवरी 2012 तक 5 लाख से अधिक अभिदाताओं का नामांकन किया गया है। इस योजना तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को समूहकर्ता (एग्रीगेटर) के रूप में

नियुक्त किया गया है तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को भी पॉइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) और समूहकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया है।

संस्थान जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है

120. अनुसंधान और नए ज्ञान का सृजन किसी आधुनिक राष्ट्र की प्रेरक शक्ति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ :

- ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को ₹ 25 करोड़;
- कोलकाता में आर्सेनिक संदूषण पर केन्द्रित करते हुए जल गुणवत्ता हेतु विश्वस्तरीय केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹ 50 करोड़;
- केरल कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़;
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक को ₹ 50 करोड़;
- हिसार कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 50 करोड़;
- ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ₹ 50 करोड़;
- हैदराबाद में आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़;
- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को ₹ 15 करोड़;
- राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर को ₹ 10 करोड़; और
- सिद्धार्थ विहार न्यास, गुलबर्गा को पालि भाषा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹ 10 करोड़;

सुरक्षा

121. वर्ष 2012-13 के बजट में रक्षा सेवाओं के लिए ₹ 1,93,407 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें पूंजी व्यय के लिए ₹ 79,579 करोड़ शामिल हैं। हमेशा की तरह, यह आवंटन वर्तमान जरूरतों पर आधारित है और भविष्य में किसी भी जरूरत को पूरा किया जाएगा।

122. सरकार सैन्य बलों के आवासीय क्वार्टरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2012-13 में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4,000 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण परिकल्पित है जिसके लिए ₹ 1,185 करोड़ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। 2012-13 के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भी ₹ 3,280 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण और 27,000 कार्मिकों को रहने के लिए बैरक शामिल हैं।

123. राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) तैयार करने की योजना अच्छी प्रगति पर है। इसके अगले दो वर्षों में पूरी होने की संभावना है। सरकार 18 वर्ष या अधिक आयु वाले सभी निवासियों को आधार नंबर के साथ निवासी पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिससे ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में मदद मिल सके।

VI. अभिशासन

मैं अब अभिशासन में आ रही कुछ चिन्ताओं के समाधान के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

यूआईडी-आधार

124. आधार प्रणाली में नामांकनों की संख्या ₹ 20 करोड़ को पार कर गई है और अब तक ₹ 14 करोड़ से अधिक आधार नम्बर सृजित किए जा चुके हैं। मैं पर्याप्त निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि 1 अप्रैल, 2012 से शुरू होने वाले अन्य ₹ 40 करोड़ नामांकन पूरे किए जा सकें। आधार प्लेटफार्म अब एमजी-नरेगा; वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन तथा छात्रवृत्तियों के भुगतान संबंधित क्षेत्रों में सीधे ही लाभार्थी के खातों में जमा करने में सहायता देने हेतु तैयार है।

काला धन

125. पिछले वर्ष मैंने काले धन के सृजन और उसके चलन की बुराई तथा भारत से बाहर इसके गैर-कानूनी अंतरण की समस्या का सामना करने के लिए एक पंच आयामी कार्यनीति को रेखांकित किया था। सरकार ने इस कार्यनीति को अमल में लाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूप :

- 82 दोहरे कराधान परिहार करार (डीटीएए) और 17 कर सूचना आदान-प्रदान करारों (टीआईई) को अंतिम रूप दिया गया है और भारतीयों द्वारा विदेशों में धारित बैंक खातों और परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त होना शुरू हो चुकी है। कुछ मामलों में अभियोजन शुरू किया जाएगा।
- संधि किए गए देशों के साथ कर सूचना के शीघ्र आदान-प्रदान हेतु समर्पित सूचना आदान-प्रदान प्रकोष्ठ सीबीडीटी में कार्य कर रहा है;
- भारत कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय सम्मेलन का 33वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है; और
- सीबीडीटी में आयकर आपराधिक अन्वेषण निदेशालय की स्थापना की गई है।

126. मैं संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी अधिप्राप्ति कानून

127. सरकार एक सरकारी अधिप्राप्ति कानून को अधिनियमित करने के प्रति बचनबद्ध है ताकि सरकारी खरीद में विश्वास बढ़ाया जा सके और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में संसद के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

128. भ्रष्टाचार-रोधी ढांचा मजबूत करने के लिए निम्नलिखित विधायी उपाय अधिनियमन के विभिन्न चरणों में हैं :

- धन शोधन रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में प्रस्तुत किया गया है ताकि इस अधिनियम के कतिपय उपबंध वैश्विक मानकों के अनुरूप हों;
- बेनामी लेन-देन (निषेध) विधेयक, 2011 की वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच की जा रही है। यह 'बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988' का स्थान लेगा; और
- राष्ट्रीय स्वापक और मनोसुख सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्वापक दवा तथा मनोसुख की सामग्री संबंधी राष्ट्रीय नीति को अमल में लाने के कानूनी उपबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके।

VII. बजट अनुमान 2012-13

मैं अब 2012-13 के बजट अनुमानों पर आता हूँ—

129. सकल कर प्राप्तियां ₹ 10,77,612 करोड़ होने का अनुमान है जो 2011-12 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.6 प्रतिशत और संशोधित अनुमानों की तुलना में 19.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर ब. अ. 2011-12 में 10.4 प्रतिशत के मुकाबले ब. अ. 2012-13 में 10.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्यों को अंतरण के पश्चात् 2012-13 में केन्द्र के निवल कर ₹ 7,71,071 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,64,614 करोड़ और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां ₹ 41,650 करोड़ हो जाने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों में पूंजी व्यय के लिए विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल की अस्थायी व्यवस्था और एक वर्ष बढ़ाकर 2012-13 तक कर दी गई है।

130. वर्ष 2012-13 हेतु कुल व्यय के लिए ₹ 14,90,925 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है। इसमें से 2012-13 के लिए आयोजना व्यय ₹ 5,21,025 करोड़ है जो 2011-12 के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत अधिक है। यह 2012-13 की बारहवीं योजना के दृष्टिकोण में अनुमानित 15 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूँ कि ग्यारहवीं योजना में, हम कुल आयोजना परिव्यय का 99 प्रतिशत पूरा करने में सफल रहे हैं।

131. वर्ष 2012-13 के आयोजना-भिन्न व्यय के लिए ₹ 9,69,900 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है जो 2011-12 के संशोधित अनुमानों से 8.7 प्रतिशत अधिक है और यह 2011-12 के बजट अनुमानों से अपेक्षाकृत 18.8 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः

प्रमुख सब्सिडियों के लिए अधिक प्रावधान किए जाने के कारण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वांछित सब्सिडियों के वित्तपोषण के लिए ग्यारहवां प्रावधान करते समय मैं संशोधित लक्ष्यों सहित किए जाने वाले उपायों के जरिए बढ़ते सब्सिडी के बोझ को हल्का करने के प्रति कृतसंकल्प हूँ।

132. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित आयोजना और आयोजना-भिन्न संसाधन, जिनमें राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण शामिल हैं। बजट अनुमान 2012-13 में 3,65,216 करोड़ रुपये हैं। इनमें 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को दिए जाने वाला ₹ 18,655 करोड़ का अनुदान शामिल है।

133. वर्ष 2011-12 राजकोषीय समेकन की कई चुनौतियों में से एक था। अपेक्षाकृत धीमे आर्थिक विकास के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रहण बजट अनुमानों से ₹ 32,000 करोड़ कम रहा। इसी के साथ, सरकार ने ₹ 49,000 करोड़ की वार्षिक राजस्व हानि के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में की गई शुल्क कटौती अवशोषित की है। सरकार को पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी पर भारी व्यय करना पड़ा था ताकि जनता को बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान की जा सके। हालांकि सब्सिडियों पर व्यय बढ़ गया है, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सब्सिडियों के स्थान पर बांड दिए जाने के बजाय पूरी राशि नकद में दी जाए। यह मेरे 2010-11 के बजट भाषण में रेखांकित किए गए दृष्टिकोण की तर्ज पर है।

134. अपेक्षाकृत कम कर और विनिवेश प्राप्तियों तथा मुख्यतः सब्सिडियों के कारण अधिक व्यय से राजकोषीय घाटा 2011-12 के संशोधित अनुमान में बढ़कर स.घ.उ. का 5.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, मैंने राजकोषीय घाटे को ₹ 5,13,590 करोड़ पर रोक कर जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है, 2012-13 के बजट में राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से वापस आने का दृढ़ प्रयास किया है। वित्तपोषण की अन्य मदों को ध्यान में रखने के पश्चात्, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारों से इस घाटे का वित्तपोषण ₹ 4.79 लाख करोड़ है। इससे 2012-13 के अन्त में कुल ऋण स्टॉक 13वें वित्त आयोग के स.घ.उ. के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में स.घ.उ. का 45.5 प्रतिशत बैठता है। ब.अ. 2012-13 में प्रभावी राजस्व घाटा ₹ 1,85,752 करोड़ बैठता है, जो स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत है।

भाग ख**VIII. कर प्रस्ताव**

अध्यक्ष महोदया,

मैं अब अपने प्रस्तावों के भाग ख पर आता हूँ।

135. वित्त मंत्री का जीवन आसान नहीं है। नीति-निर्माताओं, किसानों, राजनीतिज्ञों और व्यापारिक घरानों सहित कई खिलाड़ी अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। जब अर्थव्यवस्था के साथ सब कुछ ठीक चलता है, हम सब खुश रहते हैं। लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है तो वित्त मंत्री ही वह शख्स होता है जिसे

862 GI/12-4

गड़बड़ी सुधारने के लिए कहा जाता है। चिकित्सीय निदान की तरह अर्थव्यवस्था हमसे ऐसा कुछ करने की अपेक्षा करती है जो अल्पकालिक रूप से कष्टदायी हो सकता है लेकिन दीर्घावधिक रूप से वह हमारे भले के लिए ही होता है। जैसाकि हैमलेट, डेनमार्क के प्रिंस ने शेक्सपियर के अमर शब्दों में कहा था “दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनना ही होगा।”

यह याद दिलाने के साथ, अब मैं कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

136. पिछले वर्ष मैंने प्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष कर संहिता और अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया था। वित्त वर्ष 2012-13 के मेरे कर प्रस्ताव इस दिशा में हुई और प्रगति को परिलक्षित करते हैं।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

137. पिछले वर्ष डीटीसी दरों की तरफ बढ़ते हुए छूट सीमा बढ़ाकर मैंने वैयक्तिक करदाताओं को राहत दी थी। हालांकि डीटीसी इस वर्ष से लागू नहीं होगी, मैं आयकर के लिए डीटीसी दरों का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा को ₹1,80,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से इस श्रेणी के प्रत्येक करदाता को ₹2,000 तक की राहत मिलेगी। मैं 20 प्रतिशत की उपरि सीमा को भी ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव करता हूँ। वैयक्तिक आयकर के प्रस्तावित स्लैब इस प्रकार हैं:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ₹2 लाख तक आय | — शून्य |
| ₹2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक आय | — 10 प्रतिशत |
| ₹5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक आय | — 20 प्रतिशत |
| ₹10 लाख से अधिक आय | — 30 प्रतिशत |

इन परिवर्तनों से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

138. मैं वैयक्तिक करदाताओं को बचत बैंक खाते से मिलने वाले ब्याज के रूप में ₹10,000 तक की कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ₹5 लाख तक की वेतन आय तथा बचत बैंक खातों से ₹10,000 तक ब्याज वाले छोटे करदाताओं की बड़ी संख्या को सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें आयकर विवरणी भरना जरूरी नहीं होगा।

139. चिकित्सा बीमा के लिए अनुमत मौजूदा कटौती सीमा के भीतर, मैं निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000 तक की कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

140. चरिष्ठ नागरिक, जिन्हें कारोबार से कोई आय नहीं है, को अग्रिम कर के भुगतान से छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे उनका कर-अनुपालन बोझ भी कम होगा।

141. कारपोरेटों की स्थिति में, मैं कर दरों में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ। तथापि, अपेक्षाकृत कम लागत वाली निधियों तक कारपोरेटों की पहुँच को सुगम बनाने और कई क्षेत्रों में निवेश को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करने की अनुमति देने के लिए, मैं कई उपायों का प्रस्ताव करता हूँ।

142. दबाव वाले कुछ अवसंरचना क्षेत्रों में निम्न लागत वाली निधियाँ प्रदान करने के लिए, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज दरों पर कर रोकने की दर को तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ये क्षेत्र हैं :

- विद्युत;
- एयरलाइन;
- सड़क तथा पुल;
- पत्तन एवं पोत कारखाने;
- किफायती आवास;
- उर्वरक; और
- बांध

143. सिर्फ नौ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही निवेश करने के लिए उद्यम हेतु पूंजी निधियों पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि किसी बहुस्तरीय कारपोरेट संरचना में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) पर क्रमप्रपाती प्रभाव को हटा लिया जाए। मैं भारतीय कंपनियों की विदेशी अनुषंगी कंपनियों के लाभांशों को एक और वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक 30 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत की घटी हुई दर पर भारत में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. नीचे लिखे कारोबारों में हुए आवर्ती पूंजी व्यय के निवेश से जुड़ी कटौती को, 100 प्रतिशत की मौजूदा दर के मुकाबले, मैं 150 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

- कोल्ड चैन (शीतागार) सुविधा
- खाद्यानों के भण्डारण हेतु भाण्डागार
- अस्पताल
- उर्वरक
- किफायती आवास

145. निवेश से जुड़ी कटौती के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नए क्षेत्रों को भी जोड़ने का प्रस्ताव है।

- मधुमक्खी पालन तथा शहद और मोम उत्पादन
- कन्टेनर भाड़ा स्टेशन तथा अंतरदेशीय कन्टेनर डिपो
- चीनी भण्डारण के लिए भाण्डागार

146. अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, यह प्रस्ताव है कि इन-हाउस सुविधाओं में अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले व्यय के लिए 200 प्रतिशत की भारित कटौती को 31 मार्च, 2012 के बाद से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

147. कृषि क्षेत्र में विकास को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से, मैं कृषि-विस्तार सेवाओं के लिए किए जा रहे व्यय पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

148. विद्युत क्षेत्र के लिए, जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है, निम्न लागत वाली निधियों तक पहुँच के अलावा, मैं, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक वर्ष तक अंतिम (सनसेट) तारीख के विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे कि 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती के दावे प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 2013 को या इसके पहले वे विद्युत उपक्रमों की स्थापना कर सकें। आरम्भिक वर्ष में 20 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास को विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा अर्जित नव परिसम्पत्तियों के लिए भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

149. लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए लेखाओं की अनिवार्य कर लेखा-परीक्षा तथा उनके अनुमानित कराधान के लिए टर्न-ओवर की सीमा को ₹60 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

150. लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निधियाँ बढ़ाने हेतु, मैं, आवश्यक सम्पत्ति की बिक्री पर पूंजी अभिलाभ-कर को छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, यदि इस बिक्री से प्राप्त धन किसी नए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए किसी विनिर्माणकर्ता लघु एवं मध्यम कंपनी द्वारा इक्विटी की खरीद में प्रयुक्त हुआ है।

151. विनिर्माण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी को देखते हुए और रोजगार सृजन हेतु, मैं विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास पर हुए व्यय के 150 प्रतिशत की दर से भारित कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ।

152. पूंजी बाजारों में लेन-देन लागतों को कम करने के उद्देश्य से, मैं नकद सुपुर्दगी लेन-देनों पर प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में 20 प्रतिशत (0.125 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत) की कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

153. लाभ संबद्ध कटौतियों पर व्यय को कम करने के लिए, मैं कंपनियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों, जो लाभ संबद्ध कटौतियों का दावा करते हैं, पर अनुकल्पी न्यूनतम कर (एएमटी) लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

154. मैं आक्रामक कर परिवर्जन योजनाओं के विरुद्ध एक सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (जीएएआर) आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग समुचित मामलों में ही जीएएआर पैनल द्वारा समीक्षा करके किया जाता है।

155. बेहिसाबी धन के सृजन और उपयोग को रोकने के अनेक उपाय करने का मेरा विचार है। इसके लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:

- विदेश में धारित आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता लागू करना।

- विदेश में धारित आस्तियों के मद्दे मूल्यांकन के संबंध में आकलन को 16 वर्ष तक पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करना।

- ₹2 लाख से अधिक राशि की बुलियन अथवा आभूषण की नकद खरीद पर स्रोत पर कर संग्रहण।

- विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से ऊपर की स्थावर सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण पर स्रोत पर कर कटौती।

- कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क में व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण।

- शेयरधारकों से प्राप्त निधियों के लिए एकाधिकार वाली कम्पनियों पर प्रमाण का दायित्व बढ़ाना तथा उचित बाजार मूल्य से अधिक के शेयर प्रीमियमों पर कर लगाना।

- आय की स्लैब पर ध्यान दिए बिना, अस्पष्टीकृत धन, ऋणों, निवेशों, व्यय आदि पर 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कराधान।

156. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष ₹4500 करोड़ की निवल राजस्व हानि होने का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष कर

157. अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर आता हूँ। विगत वर्षों से जरा हटकर, मैं सेवा कर से आरम्भ करता हूँ।

सेवा कर

158. इस वर्ष जून की समाप्ति पर, इस कर के 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अतः गति बढ़ाने का समय आ गया है। तथापि, सेवा कर के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी हैं। वे हैं :

- करों में सेवाओं का हिस्सा अपनी क्षमता से काफी कम है। कर आधार को व्यापक और इसके प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; और

- सेवा कर विधि जटिल है और कभी-कभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से परिहार्य रूप से भिन्न है। हमें इन दोनों को वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन के अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यथासंभव मिला देना है।

मैंने इस वर्ष इन दोनों मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है।

159. विगत वर्ष, मैंने नकारात्मक सूची के आधार पर सेवाओं के कराधान के संबंध में आगे बढ़ने की वांछनीयता पर एक सार्वजनिक बहस की पहल की थी। अधिकांशतः तथा पूरे वर्ष जारी रही इस बहस में, हमें इस नई अवधारणा के लिए प्रबल समर्थन मिला। इसे सुदृढ़ अर्थशास्त्र और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के रूप में देखा गया है।

160. इस प्रकार, मैं, नकारात्मक सूची के वर्णित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस सूची में 17 शीर्ष हैं और ये, हमारी शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों तथा हमारी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए, ध्यानपूर्वक तैयार किए गए हैं।

161. नकारात्मक सूची में कतिपय विशिष्ट सेवाएं, जिन्हें निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करनी होती है, के सिवाए आना या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध सभी सेवाएं शामिल होती हैं। इस सूची में प्रि-स्कूल और स्कूली शिक्षा, उच्च स्तरों पर मान्यताप्राप्त शिक्षा और अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा, रिहाइशी मकानों को किराए पर देना, मनोरंजन एवं आमोद सेवाएं और अंतर्देशीय जलमार्गों, शहरी रेलवे और मीटर से चलने वाली गाड़ियों सहित सार्वजनिक परिवहन का एक बड़ा भाग भी शामिल हैं।

162. कृषि और पशुपालन का हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावहारिक रूप से, कृषि, प्रजनन, उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा विपणन प्राथमिक बाजारों में बेचे जाने वाले उत्पाद की अवस्था तक के लिए अपेक्षित सभी सेवाएं इस सूची के अंतर्गत आती हैं।

163. नकारात्मक सूची के अलावा, छूटों की भी एक सूची है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं, धार्मिक व्यक्ति, खिलाड़ी, लोक अथवा शास्त्रीय कला के कलाकार, गैर-कारोबारी कम्पनियों को सेवा दे रहे व्यक्ति अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, पशु देखभाल अथवा कार पार्किंग की सेवाएं शामिल हैं।

164. वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, मैंने व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं और बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के संपर्क व्यक्तियों की सेवाओं को भी छूट प्रदान की है।

165. विनिर्दिष्ट अवसंरचना, नहरों, सिंचाई कार्यों, फसल-पश्चात् अवसंरचना, रिहाइशी मकान और किफायती आवास योजना के तहत निम्न लागत वाले 60 वर्गमीटर के क्षेत्रफल तक के मकानों को भी छूटों में शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्तियों जो पहले से ही किसी अपार्टमेंट के स्वामी हैं, के जीवन को थोड़ा सहज बनाने के उद्देश्य से, मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य द्वारा को देय मासिक प्रभारों के लिए छूट को ₹ 3,000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

166. वर्ष 2012 की शुरुआत भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष से हुई। दादा साहिब फाल्के के "राजा हरिश्चन्द्र" से हाल में "रावन" नामक शीर्षकों में परिवर्तन के बावजूद फिल्म उद्योग ने देश की अनेक विविधताओं को होते हुए भी देश को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी समारोह मनाने की भावना को प्रेरित करते हुए, मैं उद्योग को सिनेमैटोग्राफिक रिकार्ड करने संबंधी कापीराइट पर सेवा कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

167. नकारात्मक सूची की दिशा की तरफ बढ़ने के फलस्वरूप, अभिनियम में लगभग 290 परिभाषाओं तथा विवरणों में से 54 रह

जाएंगी तथा मौजूदा 88 से घटाकर 10 रह जाने से छूट प्रदान करने से वास्तव में कुछ मौजूदा छूटों को संशोधित अधिसूचना में शामिल किया जाएगा! पृष्ठों की संख्या के सन्दर्भ में, यह कानून लगभग 40 प्रतिशत तक छोटा हो जाएगा।

168. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बीच सामंजस्य बैठाने के उपाय के रूप में, कई समन्वित प्रयास किए गए हैं। इनमें एक सामान्य सरलीकृत पंजीकरण प्रपत्र तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सामान्य विवरणी, जिसे ईएसटी-1 नाम दिया जाएगा, शामिल हैं यह सामान्य विवरणी केवल एक पृष्ठ की होगी। इससे, इस समय दो विवरणियों के 15 पृष्ठों में काफी कमी होगी।

169. सेवा कर में, संशोधन प्रार्थना पत्र प्राधिकरण तथा निपटान आयोग की शुरुआत की जा रही है जिससे ज्यादा आसानी से विवादों के निपटान में सहायता मिलेगी।

170. कैटरिंग, रेस्तरां, होटल सुविधा, पंडाल एवं शामियाना और परिवहन क्षेत्रों जैसी कई सेवाओं की संख्या में निविष्टि कर क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देकर, केसकेडिंग ऑफ टैक्सेज में काफी कमी लाई गयी है।

171. आपूर्ति नियमों के स्थान, जो सेवा प्रदान करने के स्थान को अवधारित करेंगे, को हिताधिकारियों (स्टेकहोल्डर्स) की टिप्पणियों हेतु आम जानकारी में लाया जा रहा है और नकारात्मक सूची प्रभावी होने पर उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये नियम उन सभी मुद्दों, जो वस्तु सेवा कर के अन्ततोगत्वा प्रारंभ करने हेतु अन्तर-राज्य सेवाओं के करधान में कदाचित उठ सकते हैं, का मूल्यांकन करने हेतु संसूचित चर्चा आरंभ करने के लिए एक संभावित पृष्ठभूमि भी प्रदान करेंगे।

172. मैं सेवा कर और उत्पाद शुल्क के संबंध में सामान्य कर संहिता की संभावना की जांच के लिए एक अध्ययन टीम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जो सही समय पर यथा सम्भव इन दो विधानों को सुमेलित करने के लिए यह संहिता अपनायी जा सकती है।

173. जबकि वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा निविष्टि सेवाओं पर करों के संबंध में सामने आ रही समस्याओं को इस वर्ष के प्रारम्भ में सुलझा लिया गया था, वहीं सेवा निर्यात के संबंध में करों का संचितरण काफी समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। मैं अब एक ऐसी नई योजना की घोषणा करता हूँ जो भारी-भरकम प्रलेखन अथवा साक्ष्यांकन का सहारा लिए बिना धन वापसी प्रक्रिया को सरलीकृत बनाएगी। वर्धित प्रोत्साहन के रूप में, ऐसी धनवापसियां उन कर योग्य सेवाओं पर करों के संबंध में भी अनुज्ञेय होंगी, जो छूट प्राप्त हैं।

174. करधान बिन्दु से सम्बन्धित नियमों को भी और अधिक स्पष्टता प्रदान करके तथा बाधाओं को दूर कर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में सेनवेट क्रेडिटों की पुनर्बहाली की जा रही है। कारोबार को सुगम बनाने तथा भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कई अन्य प्रस्ताव हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों पर यहां चर्चा कर इस सदन का कोमती समय नहीं लेना चाहूंगा।

175. आपको पता होगा, ये अधिकांश उपाय ऐसी व्यवस्था की तरफ मुड़ने की आवश्यकता से निर्देशित हैं जो सरल, साम्यपूर्ण तथा प्रगामी हो लेकिन इससे किसी महत्वपूर्ण तरीके से राजकोष में बढ़ोतरी करने की सम्भावना न हो। अपनी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए तथा राजकोषीय स्थिति को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए, मैं, सेवा कर दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सेवाओं की दरों में परिणामी परिवर्तन के साथ होगी तथा ये वैयक्तिक कर दरें होंगी।

176. सेवा कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से ₹18.660 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सेवाओं की सकल घरेलू उत्पाद में 59 प्रतिशत की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह प्रस्तावित बढ़ोतरी अधिक कठोर नहीं है।

मैं अब अपने अन्य अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी प्रस्तावों पर आता हूँ।

177. वर्ष 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप, मैं पेट्रोलियम-भिन्न वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क को मानक दर को चरणबद्ध तरीके से 14 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था। इस दर को बजट 2010-11 में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। राजकोषीय सुधार की अत्यावश्यकता को देखते हुए, मैं, अब मानक दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, मैरिट दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तथा लोअर मैरिट दर को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, कोयला, उर्वरक, मोबाइल फोन तथा मूल्यवान धात्विक आभूषण के लिए लोअर मैरिट दर को 1 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

178. वर्तमान में बड़ी कारों से उनकी इंजन क्षमता तथा लम्बाई के आधार पर उत्पाद शुल्क प्राप्त होता है। मानक दर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, मैं इस शुल्क को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसी कारों जिन पर प्रति वाहन 22 प्रतिशत ₹15000 की मिश्रित दर से शुल्क लगता है, के मामले में, मैं, इस शुल्क में बढ़ोतरी तथा 27 प्रतिशत की यथामूल्य दर को अपनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

179. कृषि-भिन्न वस्तुओं पर 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क की शीर्ष दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। कुछ अलग-अलग मदों को छोड़कर, शीर्ष से नीचे की दरें भी यथावत रखी जा रही हैं।

180. मैं अब विशिष्ट क्षेत्रों, खासकर जो दबाव में हैं, के लिए राहत प्रस्तावों पर आता हूँ। इन्हें निवेश की गति में तेजी लाने तथा विनिर्माण विकास हेतु तैयार किया गया है।

कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र

181. पिछले बजटों में कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण हेतु की गयी पहलकदमियों को जारी रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

- निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना :

□ गन्ना प्लांटर, मूल अथवा कन्द फसल काटने की मशीन तथा रोटरी ट्रिलर एवं वीडर;

□ इनके विनिर्माण के कल-पुर्जे;

- विनिर्दिष्ट कॉफी पौधरोपण और प्रसंस्करण मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- 5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमा शुल्क पर ग्रीन हाउस और बागवानी तथा फूलों की संरक्षित खेती-बाड़ी को परियोजना आयात लाभ देना;
- यूरिया को छोड़कर, जल में घुलनशील कुछ उर्वरकों तथा तरल उर्वरकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करना;
- मंडियों या भांडागारों में मेकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टमों और पैलेट रैकिंग सिस्टमों की स्थापना के लिए उपलब्ध रियायती आयात शुल्क बागवानी उपज के लिए देना।

182. उर्वरक परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना अथवा बड़े पैमाने पर विस्तार हेतु उपस्कर के आयात पर 31 मार्च, 2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जा रही है।

अवसंरचना

183. अवसंरचना के क्षेत्र में, मेरे प्रस्तावों में बिजली, कोयला और रेलवे के तीन क्षेत्रों में कुछ कमजोरियों पर ध्यान दिया गया है।

184. कोयले की उच्च कीमतों के कारण ताप विद्युत के घरेलू उत्पादक दबाव में रहे हैं। मैं 31 मार्च, 2014 तक दो वर्ष की अवधि के लिए स्टीम कोयले पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट और 1 प्रतिशत की रियायती सीवीडी देकर इस स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित ईंधनों को भी बुनियादी शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है :

- प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस; और
- यूरेनियम सान्द्र, प्राकृतिक और गुटिका रूप में सिटर्ड यूरेनियम डायोक्साइड।

खनन

185. खनिजों के लिए बेहतर सर्वेक्षण और पूर्वक्षेपण कार्य हमारे खनन क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं। मैं सर्वेक्षण और पूर्वक्षेपण के लिए प्रयुक्त मशीनरियों और औजारों पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, कोयला खनन परियोजनाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

862 GI/12-5

रेलवे

186. अगले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय रेलवे यात्री सुरक्षा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दो बड़ी परियोजनाएं चला रहा है। ये हैं- रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की स्थापना तथा हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरियों के ढांचे का उन्नयन। मैं इनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपस्कर पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सड़कें

187. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकारों के ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण के लिए आयातित विनिर्दिष्ट उपस्कर पर आयात शुल्क से पूर्ण छूट के लाभ का विस्तार महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा दी गई संविदाओं पर किया जा रहा है।

188. सुरंग खोदने की मशीनों और उनकी असेम्बली के लिए कल-पुर्जों को इस छूट का लाभ मिलता है। मैं, अंतिम प्रयोग की शर्त के बिना उनके शुल्क रहित आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

नागर विमानन

189. भारत में अपने आप को असेैनिक वायुयानों के तृतीय पक्ष रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ) के केंद्र के रूप में स्थापित करने की संभावना है। इस संभावना को मूर्त रूप देने के लिए, मैं इस प्रयोजन हेतु आयातित हवाई-जहाज के पुर्जों और परीक्षण उपस्करों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री को सहायता के एक उपाय के रूप में, नए और रिट्रीडेड दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट टायरों को बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

विनिर्माण

190. विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस वक्त सहारे की जरूरत है। इस क्षेत्र के लिए, मेरे प्रस्तावों में कच्चा माल, निविष्टियों, संघटकों और पूंजीगत वस्तुओं की लागत कम करके राहत देने का प्रयास किया गया है।

191. निम्न कोटि के लौह अयस्क, जिसका हमारे यहां विशाल सुरक्षित भंडार है, के परिष्करण को बढ़ावा देने हेतु, मैं लौह अयस्क गुटिका संयंत्रों या लौह अयस्क धातु परिष्करण संयंत्रों की स्थापना या बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए आयातित संयंत्र या मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी क्षेत्र से संबंधित मेरे अन्य प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं :

- निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा शुल्क घटना :
- इलेक्ट्रिकल इस्पात के विनिर्माण हेतु कोटिंग सामग्री पर 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;

- निकिल अयस्क और सान्द्र तथा निकिल आक्साइड/हाइड्रोआक्साइड पर 2.5 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत से शून्य।

- क्रोमियम अयस्क पर निर्यात शुल्क ₹3000 प्रति टन से बढ़ाकर 30 प्रतिशत यथामूल्य करना।

- गैर-मिश्र धातु, फ्लैट-रोल्ड स्टील पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करना।

192. हमारे वस्त्र उद्योग, विशेषकर बुनकर क्षेत्र को तत्काल आधुनिकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। मैं स्वचालित शटल-रहित करघों को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी तरह, स्वचालित रेशम चरखी और प्रसंस्करण मशीनरी और इसके पुर्जों को बुनियादी शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है। यह भी प्रस्ताव है कि 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क की यह छूट और मौजूदा रियायती दर केवल नई टेक्सटाइल मशीनरी तक सीमित की जाए। सेकेंड हैंड मशीनरी पर अब 7.5 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क लगेगा। वस्त्रोद्योग संबंधी अन्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

- ऊन अपशिष्ट और ऊन टॉप पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना ;
- टिटैनियम डायोक्साइड पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करना; और
- बुलेट प्रूफ हेलमेटों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त आरामिड यार्न और फैब्रिक को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना।

193. ब्रांडेड रेडीमेड परिधानों पर 10 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लागू है जिसमें फुटकर बिक्री मूल्य से 55 प्रतिशत की छूट दी जाती है। शुल्क में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ, मैं यह छूट 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप, खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में, शुल्क की दर 4.5 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत तक आ जाएगी।

194. हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र कम लागत वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए उत्तम क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं कुछ डिस्पोजेबल सामग्रियों और उपकरणों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट पुर्जों, संघटकों और कच्चे माल पर 6 प्रतिशत की रियायती सीवीडी और बुनियादी सीमा-शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोरोनरी स्टेंट्स और हृदय वाल्वों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट और सीवीडी भी दी जा रही है। ये रियायतें वास्तविक प्रयोक्ता की दशा के अध्यक्षीन होंगी।

195. विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए मेरे अन्य प्रस्तावों में ये शामिल हैं :

- निम्न पर बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट
 - रद्दी कागज; और
 - एलसीडी और एलईडी टीवी पैनल और मोबाइल फोनों के लिए मेमोरी कार्ड के पुर्जे।
- एडल्ट डायपर के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत अथवा 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना जिस पर सीवीडी 6 प्रतिशत और विशेष सीवीडी शून्य होगी।

196. मेरा ध्यान कुछ ऐसे क्षेत्रों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया गया है जो अत्यधिक श्रम प्रधान हैं और आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सहायता के उपाय के रूप में, मैं साइकिलों पर बुनियादी सीमा-शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और साइकिल के पुरजों पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

197. हाथ से बनी माचिसों पर, वर्तमान में, उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है जबकि अन्य पर मानक दर लगती है। यह प्रस्ताव है कि अर्ध-मशीनीकृत इकाइयों द्वारा विनिर्मित माचिसों पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाए।

स्वास्थ्य और पोषण

198. प्रस्ताव है कि छः विशिष्ट जीवनरक्षक दवाएं/टीके को उत्पाद-शुल्क/सीवीडी से पूर्ण छूट सहित 5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क का विस्तार किया जाए। एचआईवी-एड्स, गुर्दे का कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार अथवा निवारण के लिए प्रयोग की जाती हैं।

199. महिलाओं और बच्चों में प्रोटीन की कमी भारत में कुपोषण के सर्वाधिक मूल कारणों में एक है। मैं सोया प्रोटीन सांद्र और आइसोलेटिड सोया प्रोटीन पर बुनियादी सीमा-शुल्क क्रमशः 30 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, सभी प्रसंस्करित सोया खाद्य उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत की मेरिट दर पर किया जा रहा है।

200. आयोडिन युक्त नमक का उपभोग आयोडिन की कमी और संबद्ध बीमारियों से बचाता है। मैं आयोडिन पर 6 प्रतिशत के घटे हुए उत्पाद-शुल्क के साथ 2.5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

201. प्रोबियोटिक्स बैक्टीरिया के संक्रमण का मुकाबला करने वाले किफायती साधन हैं। यह प्रस्ताव है कि इस पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए।

पर्यावरण

202. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए, सौर तापीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की

जरूरत है। मैं ऐसी परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना हेतु संयंत्र और उपस्कर आदि को विशेष सीवीडी से पूर्णतया छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

203. ऊर्जा बचाने वाले साधनों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही रियायतें दी गई हैं। मैं काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों के लिए प्रयोग होने वाले कॉटिंग रसायन को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट का प्रस्ताव करता हूँ। एलईडी लैंपों पर भी उत्पाद शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

204. हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण हेतु आवश्यक निर्दिष्ट पुर्जे बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्णतया छूट और 6 प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क/सीवीडी के साथ विशेष सीवीडी का लाभ पा रहे हैं यह रियायत निर्दिष्ट अतिरिक्त वस्तुओं और बिजली अथवा हाइब्रिड वाहन विनिर्माताओं को आपूर्ति हेतु बैटरी पैकों के विनिर्माण हेतु आयात की गई लिथियम आयन बैटरियों पर भी दी जा रही है।

205. चालू खाता घाटे के प्राथमिक उत्प्रेरकों में से एक, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि रही है। मुझे सलाह दी गई है कि बेहतर परिणामों के लिए इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु पहले किए गए उपायों को सुदृढ़ किया जाए। मैं मानक सोने की छड़ों, 99.5 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता वाले सोने के सिक्कों और प्लैटिनम पर बुनियादी सीमा-शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और मानक-भिन्न सोने पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनके ही अनुरूप, स्वर्ण अयस्क, सान्द्र और परिष्करण हेतु डोर छड़ों पर बुनियादी शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है। उत्पाद शुल्क की ओर, परिष्कृत सोने पर शुल्क उसी अनुपात में बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जा रहा है।

206. राउन्ड ट्रिपिंग से बचने के लिए, कटे और पालिश किए हुए, रंगीन रत्न पत्थरों पर हीरों के समान 2 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त संसाधन संग्रहण

207. मैं, अब "दोषपूर्ण" वस्तु संबंधी अपने प्रस्तावों को शुरू करता हूँ। मैं विद्यमान विशिष्ट दरों में 10 प्रतिशत के यथामूल्य घटक को जोड़ते हुए 65 मि.मी. से बड़ी सिगरेटों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह यथामूल्य शुल्क पैक पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के 50 प्रतिशत पर प्रभावी होगा।

208. मैं, हाथ से बनी बीड़ियों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में सामान्य वृद्धि करते हुए ₹ 8 से ₹ 10 प्रति हजार और मशीन से बनी बीड़ियों पर ₹ 19 से ₹ 21 प्रति हजार करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। प्रति वर्ष 20 लाख बीड़ियों तक निकासियों हेतु हाथ से बनी बीड़ियों को प्राप्त विद्यमान छूट बनाए रखी जा रही है।

209. पान मसाला, गुटका चबाने वाला तंबाकू, अनिर्मित तंबाकू और थैलियों में सुगंधित जर्दे वाले तंबाकू पर मिश्रित लेवी योजना के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगता है। इन वस्तुओं के लिए प्रति पैकिंग मशीन

निर्दिष्ट शुल्क की दरें, इस उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीनों की दक्षता में सुधारों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ाई जा रही हैं।

210. भारत में उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम तेल पर तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत ₹ 2500 प्रति मीट्रिक टन का उपकर लगता है। यह दर पिछली बार 2006-07 के बजट में संशोधित की गई थी। मैं, सूचकांकन के उपाय के रूप में, उपकर की दर बढ़ाकर ₹ 4500 प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

211. एक निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऊपर की क्षमता के ईंजन वाली बड़ी कार/एमयूवी/एसयूवी और जिनकी कीमत प्रति वाहन 40,000 अमरीकी डालर से अधिक हैं, की पूर्णतया तैयार इकाइयों को टाईप अनुमोदन के बगैर, आयात की अनुमति है। ऐसे वाहनों पर बुनियादी सीमा-शुल्क यथा मूल्य 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

यौक्तिकीकरण उपाय

212. पैकेज वाली सीमेंट, चाहे मिनी-सीमेंट संयंत्रों अथवा अन्य द्वारा विनिर्मित हो, पर प्रति बोरी खुदरा बिक्री मूल्य पर निर्भर करते हुए विभेदक उत्पाद-शुल्क लगता है। यह प्रस्ताव है कि मिनी-भिन्न सीमेंट संयंत्रों के लिए 12 प्रतिशत + ₹ 120 प्रति मीट्रिक टन और मिनी-सीमेंट संयंत्रों के लिए 6 प्रतिशत + ₹ 120 प्रति मीट्रिक टन की एकीकृत दर निर्धारित की जाए। यह प्रस्ताव है कि 30 प्रतिशत की शुल्क में कटौती कम करके खुदरा बिक्री मूल्य पर यह शुल्क लगाया जाए।

213. इस सदन को स्मरण होगा कि मैंने पिछले बजट में महंगी ब्रांडेड कीमती धातुओं के आभूषणों पर। प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाए जाने की शुरुआत की थी। युक्तिकरण के उपाय के तौर पर, मैं बिना ब्रांड के आभूषणों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, इसके क्रियान्वयन को सरल करने और छोटे कारीगरों और सुनारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने के लिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि :

- यह शुल्क कारोबार मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर टैरिफ मूल्य पर लगाया ;
- लघु उद्यम को दो जाने वाली छूट पिछले वर्ष में ₹ 4 करोड़ से कम कारोबार वाली इकाइयों के लिए ₹ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार के लिए भी देना ;
- कारोबार की गणना टैरिफ मूल्य के आधार पर करना; और
- पंजीकरण और भुगतान की जिम्मेदारी जॉब वर्क पर आभूषणों के विनिर्माण करवाने वाले व्यक्ति पर डाली जाएगी।

214. मैं चांदी के ब्रांडेड आभूषण को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

215. वाणिज्यिक वाहनों की बाड़ी के निर्माण को, इस समय, उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है। इस शुल्क के स्थान पर, लागू

यथामूल्य शुल्क के अलावा चेसिस पर ₹ 10,000 की एक विशेष दर लगाई जा रही है। यह शुल्क ढांचा प्रतिगामी है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि शुल्क के इस विशेष घटक को परिवर्तित करके 3 प्रतिशत की यथामूल्य दर कर दी जाए।

216. पिछले बजट में, ड्रेजर सहित पोतों और जलयानों पर दो जाने वाली उत्पाद शुल्क छूट वापस ली गई थी। तदनुसार, 5 प्रतिशत सीवीडी इनके आयातों पर लगायी गयी थी। चूंकि विदेश जाने वाले जलयानों के आयात पर यह शुल्क लगाने की मंशा नहीं थी, इसलिए मैं, पूर्वव्यापी प्रभाव से इन जलयानों को सीवीडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में विनिर्मित पोत, जलयान और ड्रेजर को तटीय जलयानों में परिवर्तित होने वाले विदेशगामी पोतों की तुलना में, कठिनाई का सामना न करना पड़े, आवश्यक सुरक्षा मुहैया की जा रही है।

यात्री सामान भत्ता

217. विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के यात्री सामान भत्ते को पिछली बार 2004 में संशोधित किया गया था। मैं भारतीय मूल के पात्र वयस्क यात्रियों के लिए शुल्क रहित भत्ता ₹ 25,000 से बढ़ाकर ₹ 35,000 और 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹ 12,000 से बढ़ाकर ₹ 15,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

218. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों से पूरे वर्ष में ₹ 27,280 करोड़ का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

219. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष के लिए ₹ 4500 करोड़ का निवल राजस्व घाटा होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों से ₹ 45,940 करोड़ का निवल राजस्व अभिलाभ होगा और बजट में ₹ 41,440 करोड़ का निवल अभिलाभ होगा।

220. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यह वर्ष चुनौतियों से भरा रहा था। कई वैश्विक और घरेलू कारकों ने उस विकास पर हमला बोला जो पिछले दो वर्षों में किया गया था। लेकिन भारत ने चुनौतियों के चलते प्रगति की है और भारत अब भी ऐसा ही करेगा। हर संकट के बीच एक अवसर भी होता है। यह फिर से सोचने, आकलन करने और नए विचारों एवं नीतियों के लिए रास्ता बनाने का अवसर है। इसी भावना से मैंने इस वर्ष का बजट पेश किया है। इसका लक्ष्य यह है कि कारपोरेटों, किसानों, उद्यमियों और कामगारों के लिए एक समर्थकारी माहौल बनाना है ताकि जोरदार विकास के लिए पहल की जा सके। इसका लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचें। भारत एक बड़े पुनरुत्थान के मुहान पर खड़ा है। आज की गई घोषणाएँ कल सुबह के अखबारों की सुखियां बनती हैं अथवा नहीं यह कोई अहम बात नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे एक दशक के बाद के भारत को सुखियों में लाने में सहायक होंगी।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।"

शक्ति कान्ता दास, अगर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

No. F. 2(13)-B(D)/2012.—The following is published for general information :—

Budget 2012-2013

Speech of

Pranab Mukherjee

Minister of Finance

March 16, 2012

Madam Speaker,

I rise to present the Union Budget for 2012-13.

For the Indian economy, this was a year of recovery interrupted. When one year ago, I rose to present the Budget, the challenges were many, but there was a sense that the world economy was on the mend. The Budget was presented in the first glimmer of hope. But reality turned out to be different. The sovereign debt crisis in the Euro zone intensified, political turmoil in Middle East injected widespread uncertainty, crude oil prices rose, an earthquake struck Japan and the overall gloom refused to lift.

2. While I believe that there should be no room for complacency, nor any excuse for what happens in one's own country, we will be misled if we ignore the ground realities of the world. The global crisis has affected us. India's Gross Domestic Product (GDP) is estimated to grow by 6.9 per cent in 2011-12, after having grown at the rate of 8.4 per cent in each of the two preceding years. Though we have been able to limit the adverse impact of this slowdown on our economy, this year's performance has been disappointing. But it is also a fact that in any cross-country comparison, India still remains among the front runners in economic growth.

3. For the better part of the past two years, we had to battle near double-digit headline inflation. Our monetary and fiscal policy response during this period was geared towards taming domestic inflationary pressures. A tight monetary policy impacted investment and consumption growth. The fiscal policy had to absorb expanded outlays on subsidies and duty reductions to limit the pass-through of higher fuel prices to consumers. As a result growth moderated and the fiscal balance deteriorated.

4. But there is good news in the detail. With agriculture and services continuing to perform well, India's slowdown can be attributed almost entirely to weak industrial growth. While we do not have aggregate figures for the last quarter of 2011-12, numerous indicators pertaining to this period suggest that the economy is now turning around. There are signs of recovery in coal,

fertilisers, cement and electricity sectors. These are core sectors that have an impact on the entire economy. Indian manufacturing appears to be on the cusp of a revival.

5. We are now at a juncture when it is necessary to take hard decisions. We have to improve our macroeconomic environment and strengthen domestic growth drivers to sustain high growth in the medium term. We have to accelerate the pace of reforms and improve supply side management of the economy.

6. We are about to enter the first year of the Twelfth Five Year Plan which aims at "faster, sustainable and more inclusive growth." The Plan will be launched with the Budget proposals for 2012-13. In keeping with the stated priorities, I have identified five objectives that we must address effectively in the ensuing fiscal year. These are:

- Focus on domestic demand driven growth recovery;
- Create conditions for rapid revival of high growth in private investment;
- Address supply bottlenecks in agriculture, energy and transport sectors, particularly in coal, power, national highways, railways and civil aviation;
- Intervene decisively to address the problem of malnutrition especially in the 200 high-burden districts; and
- Expedite coordinated implementation of decisions being taken to improve delivery systems, governance, and transparency; and address the problem of black money and corruption in public life.

7. Today, India has global responsibilities of a kind that it did not have earlier. Our presence at the high table of global economic policy makers is a matter of some satisfaction. It, however, places new responsibilities on our shoulders. If India can continue to build on its economic strength, it can be a source of stability for the world economy and provide a safe destination for restless global capital.

8. I know that mere words are not enough. What we need is a credible roadmap backed by a set of implementable proposals to meet those objectives. In my attempt to do so, I have benefited from the able guidance of Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and strong support of the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi.

I would now begin with a brief overview of the economy.

Overview of the Economy

9. Yesterday, I laid on the table of the House the Economic Survey 2011-12, which gives a detailed analysis of the economy over the past 12 months. India's GDP is estimated to grow at 6.9 per cent in real terms in 2011-12.

862 GI/12-6

The growth is estimated to be 2.5 per cent in agriculture, 3.9 per cent in industry and 9.4 per cent in services. There is a significant slowdown in comparison to the preceding two years, primarily due to deceleration in industrial growth, more specifically in private investment. Rising cost of credit and weak domestic business sentiment, added to this decline.

10. The headline inflation remained high for most part of the year. It was only in December 2011 that it moderated to 8.3 per cent followed by 6.6 per cent in January 2012. Monthly food inflation declined from 20.2 per cent in February 2010, to 9.4 per cent in March 2011 and turned negative in January 2012. Though the February 2012 inflation figure has gone up marginally, I expect the headline inflation to moderate further in the next few months and remain stable thereafter.

11. India's inflation is largely structural, driven predominantly by agricultural supply constraints and global cost push. Evidence suggests that prolonged periods of high food inflation tend to get generalised. Fortunately, steps taken to bridge gaps in distribution, storage and marketing systems to strengthen food supply chains have helped us in a more effective management of inflation and led to a decline in food inflation.

12. The developments in India's external trade in the first half of the current year were encouraging. During April—January 2011-12, exports grew by 23 per cent to reach US Dollar 243 billion, while imports at US Dollar 391 billion recorded a growth of over 29 per cent. What is heartening is that India has successfully achieved diversification of export and import markets. The share of Asia, including ASEAN, in total trade increased from 33.3 per cent in 2000-2001 to 57.3 per cent in the first half of 2011-12. This has helped us weather the impact of global crisis emanating from Europe and to a lesser extent from USA.

13. The current account deficit as a proportion of GDP for 2011-12 is likely to be around 3.6 per cent. This, along with reduced net capital inflows in the second and third quarters, put pressure on the exchange rate.

14. Taking a bird's eye view of the entire economy and keeping in mind the difficult global environment, I expect India's GDP growth in 2012-13 to be 7.6 per cent, ± 0.25 per cent.

15. I expect average inflation to be lower next year. I also expect the current account deficit to be smaller, aided by improvement in domestic financial savings.

II. Growth

I now turn to growth and fiscal consolidation.

16. Our fiscal balance has deteriorated in 2011-12 due to slippage in direct tax revenue and increased subsidies. On both counts our underlying assumptions at the time of Budget presentation last year were belied by subsequent developments. The profit margins came under

pressure due to higher interest rates and material costs. This impacted growth in corporate taxes. Further, as against an assumption of US Dollar 90 a barrel, the average price of crude oil in 2011-12 is likely to exceed US Dollar 115. This has necessitated higher outlay on subsidies than projected. The continuing uncertainty in the global environment makes it necessary for us to strike a balance between fiscal consolidation and strengthening macroeconomic fundamentals to create adequate headroom to deal with future shocks.

Fiscal Consolidation

FRBM Act

17. The implementation of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBM Act) at Centre and the corresponding Acts at State level was the pivot in the successful consolidation of our fiscal balance prior to the global financial crisis of 2008. The outbreak of the crisis coincided with the year when the mandated targets of 3 per cent fiscal deficit and elimination of revenue deficit were to be achieved. The Government had to deviate from these targets due to injection of fiscal stimulus at that time. Following my announcement in the last Budget Speech, I am now introducing amendments to the FRBM Act as part of Finance Bill, 2012.

Expenditure Reforms

18. The fiscal targets for Centre under the amendments to the FRBM Act are indicated in the Budget documents. Meanwhile, I would like to highlight two of its features that are steps in the direction of expenditure reforms. First, the concept of Effective Revenue Deficit, introduced in the last Budget, to address the structural imbalances in the revenue account, is being brought in as a fiscal parameter. Effective Revenue Deficit is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. Focusing on this will help in reducing the consumptive component of revenue deficit and create space for increased capital spending.

19. Second, a provision for "Medium-term Expenditure Framework Statement" is being introduced in the Act. This statement shall set forth a three-year rolling target for expenditure indicators. It would help in undertaking a de-novo exercise for allocating resources for prioritised schemes and weeding out others that have outlived their utility. This would provide greater certainty in multi-year budgeting framework. It would also encourage efficiencies in expenditure management.

20. In implementing the Twelfth Plan, the recommendations made by the Expert Committees to streamline and reduce the number of Centrally Sponsored Schemes and to address Plan and Non-Plan classification, would be kept in view. The Central Plan Scheme Monitoring System would be expanded to facilitate better tracking and utilisation of funds released by the Central Government.

Subsidies

21. Fiscal consolidation calls for efforts both to raise the tax-GDP ratio and to lower the expenditure. In this context, we need to take a close look at the growth of our revenue expenditure, particularly on subsidies. The major subsidies at the Centre are for food, fertilisers and petroleum products. Some subsidies at this juncture in our development are inevitable. But they become undesirable if they compromise the macroeconomic fundamentals of the economy, more so, when they don't reach the intended beneficiaries.

22. The Government has decided that from 2012-13 subsidies related to food and for administering the Food Security Act will be fully provided for. All other subsidies would be funded to the extent that they can be borne by the economy without any adverse implications. It would be my endeavour to restrict the expenditure on Central subsidies to under 2 per cent of GDP in 2012-13. Over the next three years, it would be further brought down to 1.75 per cent of GDP. Such a step is needed to improve the quality of public spending. Our effort now will be directed towards better targeting and leakage proof delivery of the subsidies.

23. The recommendations of the task force headed by Shri Nandan Nilekani on IT strategy for direct transfer of subsidy have been accepted. Based on these recommendations, a mobile-based Fertiliser Management System (mFMS) has been designed to provide end-to-end information on the movement of fertilisers and subsidies, from the manufacturer to the retail level. This will be rolled out nation-wide during 2012. Direct transfer of subsidy to the retailer, and eventually to the farmer will be implemented in subsequent phases. This step will benefit 12 crore farmer families, while reducing expenditure on subsidies by curtailing misuse of fertilisers.

24. All the three public sector Oil Marketing Companies have launched LPG transparency portals to improve customer service and reduce leakage. A pilot project for selling LPG at market price and reimbursement of subsidy directly into the beneficiary's bank account is being conducted in Mysore. A similar pilot project on direct transfer of subsidy for kerosene into the bank accounts of beneficiaries has been initiated in Alwar district of Rajasthan. The Aadhaar platform has also been successfully used to validate PDS ration cards in Jharkhand.

25. These pilot projects show that substantial economies in subsidy outgo can be achieved by the use of Aadhaar platform. It will be our endeavour to scale up and roll out these Aadhaar enabled payments for various government schemes in at least 50 selected districts within the next six months.

Tax Reforms

26. As Hon'ble Members are aware, the Direct Taxes Code (DTC) Bill was introduced in Parliament in August 2010. It was our earnest desire to give effect to DTC from

April 1, 2012. However, we received the Report of the Parliamentary Standing Committee on March 9, 2012. We will examine the report expeditiously and take steps for the enactment of DTC at the earliest.

27. Similarly, the Constitution Amendment Bill, a preparatory step in the implementation of Goods and Services Tax (GST) was introduced in Parliament in March 2011 and is before the Parliamentary Standing Committee. As we await recommendations of the Committee, drafting of model legislation for Centre and State GST in concert with States is under progress.

28. The structure of GST Network (GSTN) has been approved by the Empowered Committee of State Finance Ministers. GSTN will be set up as a National Information Utility and will become operational by August 2012. The GSTN will implement common PAN-based registration, returns filing and payments processing for all States on a shared platform. The use of PAN as a common identifier in both direct and indirect taxes, will enhance transparency and check tax evasion. I solicit the support of all my colleagues cutting across party lines for an early passage of these landmark legislations.

Disinvestment Policy

29. The Government has further evolved its approach to divestment of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). The CPSEs are being given a level playing field vis-a-vis the private sector with regard to practices like buy-backs and listing at stock exchange. The treasury management options for CPSEs have also been enhanced. This will help improve the returns on public assets, support transparent environment for the divestment process, besides unlocking the value and resources for all stakeholders.

30. In 2011-12, as against a target of ₹40,000 crore, the Government will raise about ₹14,000 crore from disinvestment. For 2012-13, I propose to raise ₹30,000 crore through disinvestment. Let me reiterate here that while we are committed to enhancing people's ownership of CPSEs, at least 51 per cent ownership and management control will remain with the Government.

Strengthening Investment Environment

31. The domestic investment environment has suffered on multiple counts in the past year. It is time to fast track policy decisions and ensure on-time implementation of major projects.

Foreign Direct Investment

32. Organised retail helps in reducing cost of intermediation due to economies of scale, benefiting both consumers and producers. At present, FDI in single brand and in cash and carry wholesale trade is permitted to the extent of 100 per cent. The decision in respect of allowing FDI in multi-brand retail trade up to 51 per cent, subject to compliance with specified conditions, has been held in

abeyance. Efforts are on to arrive at a broad based consensus in consultation with the State Governments.

Advance Pricing Agreement

33. In a globalised economy with expanding cross-border production chains and growing trade within entities of the same group, Advance Pricing Agreement (APA) can significantly bring down tax litigation and provide tax certainty to foreign investors. Though, the provision for APA has been included in the DTC Bill, 2010, I propose to bring forward its implementation by introducing it in the Finance Bill, 2012.

Financial Sector

34. Reforms in the financial sector have been pursued with the objective of more efficient market intermediation between savers and investors.

35. To encourage flow of savings in financial instruments and improve the depth of domestic capital market, it is proposed to introduce a new scheme called Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme. The scheme would allow for income tax deduction of 50 per cent to new retail investors, who invest up to ₹50,000 directly in equities and whose annual income is below ₹10 lakh. The scheme will have a lock-in period of 3 years. The details will be announced in due course.

Capital Markets

36. During the year 2011-12, we took a series of steps to deepen the capital market and encourage investment in infrastructure sector. These steps included raising of FII investment limit in long-term infrastructure bonds, corporate bonds and government securities. The limit on External Commercial Borrowings (ECB) was also raised and qualified foreign investors were allowed to invest in specified Indian Mutual Funds and directly in equities.

37. I now propose to take the next steps in deepening the reforms in Capital market by:

- Allowing Qualified Foreign Investors (QFIs) to access Indian Corporate Bond market;
- Simplifying the process of issuing Initial Public Offers (IPOs), lowering their costs and helping companies reach more retail investors in small towns. To achieve this, in addition to the existing IPO process, I propose to make it mandatory for companies to issue IPOs of ₹10 crore and above in electronic form through nationwide broker network of stock exchanges;
- Providing opportunities for wider shareholder participation in important decisions of the companies through electronic voting facilities, besides existing process for shareholder voting, which would be made mandatory initially for top listed companies; and

- Permitting two-way fungibility in Indian Depository Receipts subject to a ceiling with the objective of encouraging greater foreign participation in Indian capital market.

Legislative Reforms

38. We have received the recommendations of the Standing Committee on Finance on "The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011", "The Banking Laws (Amendment) Bill, 2011" and "The Insurance Laws (Amendment) Bill, 2008". The official amendments to these Bills will be moved in this session of the Parliament.

39. To take forward the process of financial sector legislative reforms, the Government proposes to move the following Bills in the Budget Session of the Parliament:

- The Micro Finance Institutions (Development and Regulation) Bill, 2012;
- The National Housing Bank (Amendment) Bill, 2012;
- The Small Industries Development Bank of India (Amendment) Bill, 2012;
- National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2012;
- Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2012;
- Indian Stamp (Amendment) Bill, 2012; and
- Public Debt Management Agency of India Bill, 2012.

40. The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2011 has already been introduced in Parliament.

Capitalisation of Banks and Financial Holding Company

41. The Government is committed to protect the financial health of Public Sector Banks and financial institutions. For the year 2012-13, I propose to provide ₹15,888 crore for capitalisation of Public Sector Banks, Regional Rural Banks and other financial institutions including NABARD. The Government is also examining the possibility of creating a financial holding company which will raise resources to meet the capital requirements of Public Sector Banks.

42. To bring banking payment structure at par with global standards, a comprehensive action plan has been prepared for implementation in 2012-13. A central Know Your Customer (KYC) depository will be developed in 2012-13 to avoid multiplicity of registration and data upkeep.

Priority Sector Lending

43. A committee set up by RBI to re-examine the existing classification and suggest revised guidelines on priority sector lending has submitted its report. After stakeholder consultation, revised guidelines will be issued.

Financial Inclusion

44. In 2010-11, "Swabhimaan" campaign was launched to extend banking facilities through Business Correspondents to habitations having population in excess of 2000. I am happy to announce that out of 73,000 identified habitations that were to be covered by March, 2012, about 70,000 habitations have been provided with banking facilities. With this, over 2.55 crore beneficiary accounts would have been operationalised. The remaining habitations are likely to be covered by March 31, 2012. As a next step, Ultra Small Branches are being set up at these habitations, where the Business Correspondents would deal with cash transactions.

45. In 2012-13, I propose to extend the "Swabhimaan" campaign to habitations with population of more than 1000 in North Eastern and hilly States and to other habitations which have crossed population of 2,000 as per Census 2011.

Regional Rural Banks

46. Regional Rural Banks (RRBs) have played a crucial role in meeting the credit needs of rural areas. I am happy to inform that of the 82 RRBs in India, 81 have successfully migrated to Core Banking Solutions (CBS) and have also joined the National Electronic Fund Transfer system.

47. The Government had initiated the process of capitalisation of 40 financially weak RRBs, which has been completed in respect of 12 RRBs by the end of February, 2012. I propose to extend the scheme of capitalisation of weak RRBs by another 2 years to enable all the States to contribute their share.

III. Infrastructure and Industrial Development

Let me now turn to infrastructure and industrial development.

48. Lack of adequate infrastructure is a major constraint on our growth. The strategy we have followed so far is to increase investment in infrastructure through a combination of public investment and public private partnerships (PPP). During the Twelfth Plan period, infrastructure investment will go up to ₹50 lakh crore. About half of this is expected to come from private sector.

49. Viability Gap Funding (VGF) under the Scheme for Support to PPP in infrastructure is an important instrument in attracting private investment into the sector. This year it has been decided to make irrigation (including dams, channels and embankments), terminal markets, common infrastructure in agriculture markets, soil testing laboratories and capital investment in fertiliser sector eligible for VGF under this scheme. Oil and Gas/LNG storage facilities and oil and gas pipelines, fixed network for telecommunication and telecommunication towers will also be made eligible sectors for VGF.

50. The Government has approved guidelines for establishing joint venture companies by defence Public Sector Undertakings in PPP mode. This will serve the dual purpose of achieving substantive self-reliance in the defence sector and production of state-of-the-art defence goods.

51. I had announced the setting up of Infrastructure Debt Funds to tap the overseas markets for long tenor pension and insurance funds. I am happy to inform the House that the first Infrastructure Debt Fund with an initial size of ₹8000 crore, has been launched earlier this month.

52. For the year 2011-12, tax-free bonds for ₹30,000 crore were announced for financing infrastructure projects. I propose to double it to raise ₹ 60,000 crore in 2012-13. This includes ₹ 10,000 crore for NHAI, ₹ 10,000 crore for IRFC, ₹ 10,000 crore for IIFCL, ₹ 5,000 crore for HUDCO, ₹ 5,000 crore for National Housing Bank, ₹ 5,000 crore for SIDBI, ₹ 5,000 crore for ports and ₹ 10,000 crore for power sector.

53. A harmonised master list of infrastructure sector has been approved by the Government. This will help in removing ambiguity in the policy and regulatory domain and encourage investment in the infrastructure sector.

54. To ease access of credit to infrastructure projects, India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) has put in place a structure for credit enhancement and take-out finance. A consortium for direct lending and grant of in-principle approval to developers before the submission of bids for PPP projects has also been created.

National Manufacturing Policy

55. The Government has announced a National Manufacturing Policy on October 25, 2011 with the objective of raising, within a decade, the share of manufacturing in GDP to 25 per cent and creation of 10 crore jobs. The Policy encourages the setting-up of National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs) across the country.

56. I will now address some issues that have impacted infrastructure and industrial activity in the past months.

Power and Coal

57. In power generation, fuel supply constraints are affecting production prospects. To address this concern, Coal India Limited (CIL) has been advised to sign fuel supply agreements, with power plants that have entered into long-term Power Purchase Agreements with DISCOMs and would get commissioned on or before March 31, 2015. An inter-ministerial group is being constituted to undertake periodic review of the allocated coal mines and make recommendations on de-allocation, if so required.

58. I propose to allow External Commercial Borrowings (ECB) to part finance Rupee debt of existing power projects.

862 GI/12-7

Transport: Roads and Civil Aviation

59. The Ministry of Road Transport and Highways is set to achieve its target of awarding projects covering a length of 7,300 km under NHDP during 2011-12. This would be 44 per cent higher than the best ever length of 5,082 km awarded in 2010-11. Of the 44 projects awarded during 2011-12, 24 projects have fetched a premium. I propose to set a target of covering a length of 8,800 kms under NHDP next year. The allocation of the Ministry has been enhanced by 14 per cent to ₹25,360 crore in 2012-13.

60. To encourage public private partnerships in road construction projects, I propose to allow ECB for capital expenditure on the maintenance and operations of toll systems for roads and highways so long as they are a part of the original project.

61. The airline industry is facing financial crisis. The high operating cost of the sector is largely attributable to the cost of Aviation Turbine Fuel (ATF). To reduce the cost of ATF, Government has permitted direct import of ATF by Indian Carriers, as actual users.

62. To address the immediate financing concerns of the Civil Aviation sector, I propose to permit ECB for working capital requirements of the airline industry for a period of one year, subject to a total ceiling of US Dollar 1 billion.

63. A proposal to allow foreign airlines to participate up to 49 per cent in the equity of an air transport undertaking engaged in operation of scheduled and non-scheduled air transport services is under active consideration of the Government.

Delhi Mumbai Industrial Corridor

64. The Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) is being developed on either side along the alignment of the Western Dedicated Rail Freight Corridor. The project has made significant progress. In September 2011, Central assistance of ₹ 18,500 crore spread over a period of 5 years has been approved. The Japanese Prime Minister has announced US\$ 4.5 billion as Japanese participation in DMIC project.

Housing sector

65. In view of the shortage of housing for low income groups in major cities and towns, I propose to:

- Allow ECB for low cost affordable housing projects;
- Set up Credit Guarantee Trust Fund to ensure better flow of institutional credit for housing loans;
- Enhance provisions under Rural Housing Fund from ₹ 3000 crore to ₹ 4000 crore;
- Extend the scheme of interest subvention of 1 per cent on housing loan up to ₹15 lakh where

the cost of the house does not exceed ₹25 lakh for another year; and

- Enhance the limit of indirect finance under priority sector from ₹5 lakh to ₹10 lakh.

Fertilisers

66. To reduce India's import dependence in urea, Government has taken steps to finalise pricing and investment policies for urea. It is expected that with the implementation of the investment policy, country will become self-sufficient in manufacturing urea in the next five years. In case of the potassic-phosphatic (P&K) fertiliser, use of single super phosphate (SSP) will be encouraged through greater extension work. This fertiliser is manufactured entirely in the domestic sector. Enhanced production would bring down our dependence on imports in the P & K sector.

Textiles

67. The Government has recently announced a financial package of ₹3,884 crore for waiver of loans of handloom weavers and their cooperative societies.

68. In addition to 4 mega handloom clusters already operationalised, I am now happy to announce two more mega clusters, one to cover Prakasam and Guntur districts in Andhra Pradesh and the other for Gadga and neighbouring districts in Jharkhand. I also propose to provide assistance in setting up of dormitories for women workers in the 5 mega clusters relating to handloom, powerloom and leather sectors.

69. The Ministry of Textiles runs Weavers' Service Centres in different parts of the country for providing technical support to poor handloom weavers. I propose to set up three such Centres, one each in Mizoram, Nagaland and Jharkhand. I am also happy to announce ₹500 crore pilot scheme in the Twelfth Plan for promotion and application of Geo-textiles in the North East Region.

70. To address the need of the local artisans and weavers, I propose to set up a powerloom mega cluster in Ichalkaranji in Maharashtra with a Budget allocation of ₹70 crore.

Micro, Small and Medium Enterprises

71. In order to enhance availability of equity to MSME sector, I propose to set up a ₹5,000 crore India Opportunities Venture Fund with SIDBI.

72. The Small and Medium Enterprises (SMEs) are the building blocks of our economy. They rely primarily on loans from banks and informal sources to raise capital. To enable these enterprises greater access to finance, two SME exchanges have been launched in Mumbai recently.

Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

73. With the objective of promoting market access of Micro and Small Enterprises, Government has approved

a policy which requires Ministries and CPSEs to make a minimum of 20 per cent of their annual purchases from MSEs. Of this, 4 per cent will be earmarked for procurement from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs.

IV. Agriculture

I now take up agriculture.

74. Agriculture will continue to be a priority for the Government. The total plan outlay for the Department of Agriculture and Cooperation is being increased by 18 per cent from ₹ 17,123 crore in 2011-12 to ₹ 20,208 crore in 2012-13.

75. The outlay for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is being increased from ₹ 7,860 crore in 2011-12 to ₹ 9,217 crore in 2012-13. I am happy to inform the House that the initiative of Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI) has resulted in a significant increase in production and productivity of paddy. States in Eastern India have reported additional paddy production of seven million tonnes in Kharif 2011. I propose to increase the allocation for this scheme from ₹ 400 crore in 2011-12 to ₹ 1000 crore in 2012-13.

76. This year, under RKVY, I also propose to allocate ₹ 300 crore to Vidarbha Intensified Irrigation Development Programme. This Scheme seeks to bring in more farming areas under protective irrigation.

77. The Government intends to merge the remaining activities into a set of missions to address the needs of agricultural development in the Twelfth Five Year Plan. These Missions are :

- (i) National Food Security Mission which aims to bridge the yield gap in respect of paddy, wheat, pulses, millet and fodder. The ongoing Integrated Development of Pulses Villages, Promotion of Nutri-cereals and Accelerated Fodder Development Programme would now become a part of this Mission;
- (ii) National Mission on Sustainable Agriculture including Micro Irrigation is being taken up as a part of the National Action Plan on Climate Change. The Rainfed Area Development Programme will be merged with this;
- (iii) National Mission on Oil seeds and Oil Palm aims to increase production and productivity of oil seeds and oil palm;
- (iv) National Mission on Agricultural Extension and Technology focuses on adoption of appropriate technologies by farmers for improving productivity and efficiency in farm operations; and
- (v) National Horticulture Mission aims at horticulture diversification. This will also include the initiative on saffron.

National Mission for Protein Supplement

78. Mission for Protein Supplement is being strengthened. To improve productivity in the dairy sector, a ₹ 2,242 crore project is being launched with World Bank assistance. To broaden the scope of production of fish to coastal aquaculture, apart from fresh water aquaculture, the outlay in 2012-13 is being stepped up to ₹ 500 crore. Suitable allocations are also being made for poultry, piggery and goat rearing.

Agriculture Credit

79. Farmers need timely access to affordable credit. I propose to raise the target for agricultural credit in 2012-13 to ₹ 5,75,000 crore. This represents an increase of ₹ 1,00,000 crore over the target for the current year.

80. The interest subvention scheme for providing short term crop loans to farmers at 7 per cent interest per annum will be continued in 2012-13. An additional subvention of 3 per cent will be available to prompt paying farmers. In addition, the same interest subvention on post harvest loans up to six months against negotiable warehouse receipt will also be available. This will encourage the farmers to keep their produce in warehouses.

81. A Short term RRB Credit Refinance Fund is being set-up to enhance the capacity of Regional Rural Banks to disburse short term crop loans to the small and marginal farmers. I propose to allocate ₹ 10,000 crore to NABARD for refinancing the RRBs through this fund.

82. Kisan Credit Card (KCC) is an effective instrument for making agricultural credit available to the farmers. KCC scheme will be modified to make KCC a smart card which could be used at ATMs.

Agricultural Research

83. Food security and agricultural development in the coming decades would depend upon scientific and technological breakthroughs in raising productivity. We have to develop plant and seed varieties that yield more and can resist climate change. I propose to set aside a sum of ₹ 200 crore for incentivising research with rewards, both for institutions and the research team responsible for such scientific breakthroughs.

Irrigation

84. Unless we recognise water as a resource, the day is not far when water stress will start threatening our agricultural production. Focus on micro irrigation schemes to dovetail these with water harvesting schemes is necessary. To maximise the flow of benefits from investments in irrigation projects, structural changes in Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) are being made. The allocation for AIBP in 2012-13 is being stepped up by 13 per cent to ₹ 14,242 crore.

85. To mobilise large resources to fund irrigation projects, a Government owned Irrigation and Water

Resource Finance Company is being operationalised. The Company would start its operations in 2012-13 by focusing on financing sub-sectors like micro-irrigation, contract farming, waste water management and sanitation.

86. A flood management project for Kandi sub-division of Murshidabad District has been approved by the Ganga Flood Control Commission at a cost of ₹ 439 crore, to be taken up for funding under the Flood Management Programme.

National Mission on Food Processing

87. The food processing sector has been growing at an average rate of over 8 per cent over the past 5 years. In order to have a better outreach and to provide more flexibility to suit local needs, it has been decided that a new centrally sponsored scheme titled "National Mission on Food Processing" would be started, in cooperation with the State Governments in 2012-13.

88. The Government has taken steps to create additional foodgrain storage capacity in the country. Creation of 2 million tonnes of storage capacity in the form of modern silos has already been approved. Nearly 15 million tonnes capacity is being created under the Private Entrepreneur's Guarantee Scheme, of which 3 million tonnes of storage capacity will be added by the end of 2011-12 and 5 million would be added next year.

V. Inclusion

Let me now take up proposals for inclusive development.

Scheduled Castes and Tribal Sub Plans

89. From the year 2011-12, allocations are being made for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) and Tribal Sub Plan (TSP) under separate minor heads as part of the Plan allocations. In 2012-13, the allocation for SCSP is ₹ 37,113 crore which represents an increase of 18 per cent over 2011-12. The allocation for TSP in 2012-13 is ₹ 21,710 crore representing an increase of 17.6 per cent over 2011-12.

Food Security

90. Our Government has taken definite steps to create food security at the household level by making food a legal entitlement for all targeted people, especially for the poor and vulnerable segments of our population. The National Food Security Bill, 2011 is before the Parliamentary Standing Committee.

91. To ensure that the objectives of the National Food Security Bill are effectively realised, a Public Distribution System Network is being created using the Aadhaar platform. A National Information Utility for the computerisation of PDS is being created. It will become operational by December 2012.

Multi-sectoral Nutrition Augmentation Programme

92. Following the decision taken in the Prime Minister's National Council on India's Nutritional

Challenges, a multi-sectoral programme to address maternal and child malnutrition in selected 200 high burden districts is being rolled out during 2012-13. It will harness synergies across nutrition, sanitation, drinking water, primary health care, women education, food security and consumer protection schemes.

93. In this context, Integrated Child Development Services (ICDS) scheme is being strengthened and re-structured. For 2012-13, an allocation of ₹ 15,850 crore has been made as against ₹ 10,000 crore in 2011-12. This amounts to an increase of over 58 per cent.

94. National Programme of Mid Day Meals in Schools has enhanced enrolment, retention, attendance, and also helped in improving nutrition levels among children. In 2012-13, I propose to allocate ₹ 11,937 crore for this scheme as against 10,380 crore in 2011-12.

95. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls, SABLA, has been introduced last year with a view to address the nutritional needs and other educational and skill development initiatives for self-development of adolescent girls in the age group of 11 to 18 years. For 2012-13, an allocation of ₹ 750 crore has been proposed for the scheme.

Rural Development and Panchayati Raj

96. Along with water quality, poor sanitation is one of the factors contributing to malnourishment. Hon'ble Members will be happy to know that I propose to increase the budgetary allocation for rural drinking water and sanitation from ₹ 11,000 crore in 2011-12 to ₹ 14,000 crore in 2012-13. This is an increase of over 27 per cent.

97. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) has been a successful programme. In 2012-13, I propose to raise the allocation by 20 per cent to this scheme by providing ₹ 24,000 crore. It will accelerate connectivity in the States.

98. A major initiative has been proposed to strengthen Panchayats across the country through the Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA). This programme will expand on the existing schemes for Panchayat capacity building.

99. In my Budget Speech last year, I had referred to our focus on the development of backward regions. We have decided to carry the Backward Regions Grant Fund scheme into the Twelfth Plan with an enhanced allocation of ₹ 12,040 crore in 2012-13, an increase of about 22 per cent over BE of 2011-12. This includes the State component which covers projects in backward areas in Bihar, West Bengal and the Kalahandi-Bolangir-Koraput region of Odisha, development projects for drought mitigation in the Bundelkhand region and projects under the Integrated Action Plan to accelerate the pace of development in selected tribal and backward districts.

Rural Infrastructure Development Fund

100. This year, I propose to enhance the allocation under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to ₹20,000 crore. Further in view of the warehousing shortage in the country, I propose to earmark an amount of ₹5,000 crore from the above allocation exclusively for creating warehousing facilities under RIDF.

Education

101. The Right to Education (RTE) Act is being implemented with effect from April 1, 2010 through the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). For 2012-13, I have provided ₹25,555 crore for RTE-SSA. This is an increase of 21.7 per cent over 2011-12.

102. In the Twelfth Plan, 6,000 schools have been proposed to be set up at block level as model schools to benchmark excellence. Of these, 2500 will be set up under Public Private Partnership.

103. The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) was launched in March, 2009 to enhance access to quality secondary education. In 2012-13, I have allocated ₹3,124 crore for RMSA which is nearly 29 per cent higher than the allocation in 2011-12.

104. A scheme for education loans is being implemented by banks. To ensure better flow of credit to deserving students, I propose to set up a Credit Guarantee Fund for this purpose.

Health

105. They say persistence pays. I am happy to inform Hon'ble Members that no new case of polio was reported in the last one year. By modernising existing units and setting up a new integrated vaccine unit near Chennai, the Government will achieve vaccine security and keep the pressure on disease eradication and prevention.

106. National Rural Health Mission (NRHM) is being implemented through 'Accredited Social Health Activist' — 'ASHA'. The scope of ASHA's activities is being enlarged to include prevention of Iodine Deficiency Disorders, ensure 100 per cent immunisation and better spacing of children. At the community level, a more active role is envisaged for ASHA as the convenor of the Village Health and Sanitation Committee, as also to support the initiative on malnutrition. Since ASHAs receive activity-wise, performance-based payments, this will also enhance their remuneration. I propose to increase the allocation to NRHM from ₹18,115 crore in 2011-12 to ₹20,822 crore in 2012-13.

107. National Urban Health Mission is being launched to encompass the primary healthcare needs of people in the urban areas. The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) aimed at setting up of AIIMS-like institutions and upgradation of existing Government

medical colleges is being expanded to cover upgradation of 7 more Government medical colleges. It will enhance the availability of affordable tertiary health care.

Employment and Skill Development

108. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has had a positive impact on livelihood security. For the first time, there is an effective floor wage rate for rural workers. Distress migration has come down. Community assets have been created. Productivity of barren and fallow lands has gone up. The need for improving quality of assets and bringing about greater synergy between MG-NREGA and agriculture and allied rural livelihoods is being addressed.

109. The Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) has been restructured into National Rural Livelihood Mission (NRLM) to provide self-employment opportunities. A sub-component, Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana, under NRLM seeks to provide better targeting of women farmers. For NRLM, I propose to increase the allocation by over 34 per cent from ₹2,914 crore in 2011-12 to ₹3,915 crore in 2012-13.

110. In last year's Budget I had announced creation of a 'Women's SHG's Development Fund'. This has been set up in NABARD. In 2012-13, I propose to provide ₹200 crore to enlarge the corpus to ₹300 crore. This Fund will also support the objectives of Aajeevika i.e. the National Rural Livelihood Mission. It will empower women SHGs to access bank credit. I propose to provide interest subvention to Women SHGs to avail loans up to ₹3 lakh at 7 per cent per annum. Women SHGs that repay loans in time will get additional 3 per cent subvention, reducing the effective rate to 4 per cent. The initiative, in the first phase, would focus on selected 600 Blocks of 150 districts, including the Left Wing Extremism affected districts.

111. It is proposed to establish a Bharat Livelihoods Foundation of India through Aajeevika. The Foundation would support and scale up civil society initiatives and interventions particularly in the tribal regions covering around 170 districts. Private trusts and philanthropic organisations would be encouraged to partner with the autonomous body that will be managed professionally.

112. To encourage micro enterprises, a credit linked subsidy programme namely Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is being implemented through KVIC. The allocation for this programme has been increased by 23 per cent from ₹1,037 crore in 2011-12 to ₹1,276 crore in 2012-13.

Skill Development

113. In 2011-12 National Skill Development Corporation (NSDC) approved 26 new projects, thereby doubling the number of projects sanctioned since 2009 to 52, with a total funding commitment of ₹1,205 crore. At the end of 10 years, these projects are expected to train 6.2 crore persons and augment vocational training capacity by 1.25 crore per year in the private sector.

862 GI/12-8

114. The NSDC partners have opened 496 permanent and 2429 mobile centres in 220 districts across 24 states. More than 89,500 persons have been trained and almost 80 per cent employed. Under NSDC, 10 Sector Skill Councils have been sanctioned. Of these, 3 Skill Councils for Automobile, Security and Retail sectors have become operational. For 2012-13, I propose to allocate ₹ 1000 crore to National Skill Development Fund (NSDF).

115. In order to improve the flow of institutional credit for skill development, I propose to set up separate Credit Guarantee Fund. This will benefit youth in acquiring market oriented skills.

116. A new scheme titled "Himayat" was introduced in Jammu and Kashmir from 2011-12. It aims to provide skill training to one lakh youth in the next five years. The entire cost of this programme is being borne by the Centre.

Social security and the needs of weaker sections

117. I am raising the allocation under the National Social Assistance Programme (NSAP) by 37 per cent from ₹ 6,158 crore in 2011-12 to ₹ 8,447 crore in 2012-13. Under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme for BPL beneficiaries, the monthly pension amount per person is being raised from ₹ 200 to ₹ 300.

118. On the death of the primary breadwinner of a BPL family, in the age group 18 to 64 years, a lumpsum grant of ₹ 10,000 is presently provided under the National Family Benefit scheme. I propose to double this amount to ₹ 20,000 and expect a matching contribution by the State Governments.

119. In order to promote voluntary savings towards pensions, a co-contributory scheme SWAVALAMBAN was started in September, 2010. Over 5 lakh subscribers have been enrolled by February 2012. In order to enhance access to this scheme, LIC has been appointed as an Aggregator and all Public Sector Banks have also been appointed as Points of Presence (PoP) and Aggregators.

Institutions that are being given grants

120. The driving force of a modern nation is research and the creation of new knowledge. With this in mind I propose to provide:

- ₹ 25 crore to the Institute of Rural Management, Anand;
- ₹ 50 crore to establish a world-class centre for water quality with focus on arsenic contamination in Kolkata;
- ₹ 100 crore to Kerala Agricultural University;
- ₹ 50 crore for University of Agricultural Sciences Dharwad, Karnataka;
- ₹ 50 crore to Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hissar;
- ₹ 50 crore to Orissa University of Agriculture and Technology;
- ₹ 100 crore to Acharya N. G Ranga Agricultural University in Hyderabad;
- ₹ 15 crore to National Council for Applied Economic Research;
- ₹ 10 crore to Rajiv Gandhi University, Department of Economics, Itanagar; and
- ₹ 10 crore to Siddharth Vihar Trust Gulbarga, to establish a Pali language Research Centre.

Security

121. In the Budget for 2012-13, a provision of ₹ 1,93,407 crore has been made for Defence Service which include ₹ 79,579 crore for capital expenditure. As always, this allocation is based on present needs and any further requirement would be met.

122. Government is making efforts to increase the availability of residential quarters to forces. In 2012-13, it is envisaged to construct nearly 4,000 residential quarters for Central Armed Police Forces for which ₹ 1,185 crore is proposed to be allocated. A provision of ₹ 3,280 crore for 2012-13 has also been made for construction of office buildings including land acquisition and barracks to accommodate 27,000 personnel.

123. The scheme to create the National Population Register (NPR) is progressing well. It is likely to be completed within the next two years. The Government is also considering a proposal of issuing Resident Identity Cards bearing the Aadhaar numbers to all residents who are of age 18 years and above to help in the e-governance initiatives.

VI. Governance

I now address some concerns in governance.

UID-Aadhaar

124. The enrolments into the Aadhaar systems have crossed 20 crore and the Aadhaar numbers generated upto date have crossed 14 crore. I propose to allocate adequate funds to complete another 40 crore enrolments starting from April 1, 2012. The Aadhaar platform is now ready to support the payments of MG-NREGA; old age, widow and disability pensions; and scholarships directly to the beneficiary accounts in selected areas.

Black Money

125. Last year I had outlined a five pronged strategy to tackle the malaise of generation and circulation of black money and its illegitimate transfer outside India. Government has taken a number of proactive steps to implement this strategy. As a result:

- 82 Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) and 17 Tax Information Exchange Agreements (TIEA) have been finalised and

information regarding bank accounts and assets held by Indians abroad has started flowing in. In some cases prosecution will be initiated;

- Dedicated exchange of information cell for speedy exchange of tax information with treaty countries is fully functional in CBDT;
- India became the 33rd signatory of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters; and
- Directorate of Income Tax Criminal Investigation has been established in CBDT.

126. I propose to lay on the table of the House a white paper on Black Money in the current session of Parliament.

Public Procurement Legislation

127. Government is committed to the enactment of a Public Procurement legislation to enhance confidence in public procurement and to ensure transparency and efficiency in the process. The Bill in this regard is to be introduced in the Budget session of the Parliament.

128. The following legislative measures for strengthening anti-corruption framework are in various stages of enactment:

- Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011 introduced in Parliament with a view to bring certain provisions of the Act in line with global standards;
- Benami Transactions (Prohibition) Bill, 2011 is currently being examined by the Standing Committee on Finance. It would replace the 'Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988'; and
- National Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2011 introduced in Parliament with a view to strengthen legal provisions for implementation of the national policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

VII. Budget Estimates 2012-13

I now turn to the Budget Estimates for 2012-13.

129. The Gross Tax Receipts are estimated at ₹10,77,612 crore which is an increase of 15.6 per cent over the Budget Estimates and 19.5 per cent over the Revised Estimates for 2011-12. As a percentage of GDP, gross taxes are estimated at 10.6 per cent in BE 2012-13 as against 10.4 per cent in BE 2011-12. After devolution to States, the net tax to Centre in 2012-13 is estimated at ₹7,71,071 crore. The Non Tax Revenue Receipts for 2012-13 are estimated at ₹1,64,614 crore and Non-debt Capital Receipts at ₹41,650

crore. The temporary arrangement to use disinvestment proceeds for capital expenditure in social sector schemes is being extended for one more year to 2012-13.

130. The total expenditure for 2012-13 is budgeted at ₹14,90,925 crore. Of this, the Plan Expenditure for 2012-13 is ₹5,21,025 crore, which is 18 per cent higher than the Budget Estimates of 2011-12. This is higher than the 15 per cent increase projected in the Approach to the Twelfth Plan for 2012-13. I am happy to inform the Hon'ble Members that in the Eleventh Plan, we have been able to meet 99 per cent of the total plan outlay.

131. The Non Plan Expenditure for 2012-13 is budgeted at ₹9,69,900 crore which is 8.7 per cent higher than the Revised Estimates for 2011-12 and 18.8 per cent higher than the Budget Estimates for 2011-12. This increase is mainly on account of higher provision for major subsidies. While making adequate provisions for funding the desirable subsidies, as indicated earlier, I am determined to contain the increasing subsidy burden through measures including improved targeting.

132. The Plan and Non Plan resources transferred to States and Union Territories including direct transfers to State and district level implementing agencies are ₹3,65,216 crore in BE 2012-13. This includes ₹18,655 crore of grant to local bodies as per the recommendations of Thirteenth Finance Commission.

133. The year 2011-12 was one of challenges for fiscal management. Due to the slower economic growth, direct tax collection fell short by ₹32,000 crore of the Budget Estimates. At the same time, the Government absorbed duty reduction in petroleum sector with annual revenue loss of ₹49,000 crore. The Government had to incur higher expenditure on petroleum and fertiliser subsidy to insulate the people from the rising prices. While the outgo on account of subsidies increased, I have ensured that the entire amount is given in cash and not as bonds in lieu of subsidies. This is in line with the approach that I outlined in my Budget Speech for 2010-11.

134. The combined effect of lower tax and disinvestment receipts and higher expenditure, mainly on account of subsidies, has pushed the fiscal deficit to 5.9 per cent of GDP in the Revised Estimates for 2011-12. However, I have made a determined attempt to come back to the path of fiscal consolidation in the Budget for 2012-13 by pegging the fiscal deficit at ₹5,13,590 crore which is 5.1 per cent of GDP. After taking into account other items of financing, the net market borrowings through dated securities to finance this deficit is ₹4.79 lakh crore. With this, the total Debt stock at the end of 2012-13 would work out at 45.5 per cent of GDP as compared to the Thirteenth Finance Commission target of 50.5 per cent of GDP. The Effective Revenue Deficit in BE 2012-13 works out to ₹1,85,752 crore which is 1.8 per cent of GDP.

Part B
VIII. Tax Proposals

Madam Speaker,

I now come to Part B of my proposals.

135. The life of a Finance Minister is not easy. Various players, including policy makers, politicians, agriculturists and business houses, participate in the making of the economy. When everything goes well with the economy, we all share in the joy. However, when things go wrong, it is the Finance Minister who is called upon to administer the medicine. Economic policy, as in medical treatment, often requires us to do something, which, in the short run, may be painful, but is good for us in the long run. As Hamlet, the Prince of Denmark, had said in Shakespeare's immortal words. "I must be cruel only to be kind."

With this reminder, let me now turn to the tax proposals.

136. Last year, I had set the compass for movement towards the DTC in Direct Taxes and GST in Indirect Taxes. My tax proposals for fiscal year 2012-13 mark further progress in that direction.

Direct Taxes

I shall now deal with direct taxes.

137. Last year I provided relief to individual taxpayers by enhancing the exemption limit as a move towards DTC rates. Although DTC will not be effective from this year, I propose to introduce the DTC rates for personal income tax. I propose to enhance the exemption limit for the general category of individual taxpayers from ₹1,80,000 to ₹2,00,000. This measure will provide tax relief upto ₹2,000 to every taxpayer of this category. I also propose to raise the upper limit of the 20 per cent tax slab from ₹8 lakh to ₹10 lakh. The proposed personal income tax slabs are :

| | |
|--|-------------|
| Income upto ₹2 lakh | Nil |
| Income above ₹2 lakh and upto ₹5 lakh | 10 per cent |
| Income above ₹5 lakh and upto ₹10 lakh | 20 per cent |
| Income above ₹10 lakh | 30 per cent |

These changes will provide substantial relief to taxpayers.

138. I propose to allow individual taxpayers, a deduction of up to ₹10,000 for interest from savings bank accounts. This would help a large number of small taxpayers with salary incomes upto ₹5 lakh and interest from saving bank accounts up to ₹10,000, as they would not be required to file income tax returns.

139. Within the existing limit for deduction allowed for health insurance, I propose to allow a deduction of upto ₹5,000 for preventive health check-up.

140. Senior citizens who do not have any income from business are proposed to be exempted from the payment of advance tax. This will reduce their compliance burden.

141. In the case of corporates, I am not proposing any change in the tax rates. However, I propose certain measures to allow corporates to access lower cost funds and to promote higher level of investments in several sectors.

142. In order to provide low cost funds to some stressed infrastructure sectors, the rate of withholding tax on interest payments on external commercial borrowings is proposed to be reduced from 20 per cent to 5 per cent for three years. These sectors are:

- power;
- airlines;
- roads and bridges;
- ports and shipyards;
- affordable housing;
- fertilizer; and
- dams

143. The restriction on Venture Capital Funds to invest only in nine specified sectors is proposed to be removed. It is further proposed to remove the cascading effect of Dividend Distribution Tax (DDT) in a multi-tier corporate structure. I also propose to continue to allow repatriation of dividends from foreign subsidiaries of Indian companies to India at a lower tax rate of 15 per cent as against the tax rate of 30 per cent for one more year i.e. upto March 31, 2013.

144. Investment linked deduction of capital expenditure incurred in the following businesses is proposed to be provided at the enhanced rate of 150 per cent, as against the current rate of 100 per cent.

- Cold chain facility
- Warehouses for storage of food grains
- Hospitals
- Fertilisers
- Affordable housing

145. The following new sectors are proposed to be added for the purposes of investment linked deduction:

- bee keeping and production of honey and beeswax
- container freight station and inland container depots
- warehousing for storage of sugar

146. To promote investment in research and development, it is proposed to extend the weighted deduction of 200 per cent for R&D expenditure in an in-house facility beyond March 31, 2012 for a further period of five years.

147. I also propose to provide weighted deduction of 150 per cent on expenditure incurred for agri-extension

services in order to facilitate growth in the agriculture sector.

148. For the power sector, besides access to low cost funds as outlined above, I also propose extension of the sunset date by one year for power sector undertakings so that they can be set up on or before March 31, 2013 for claiming 100 per cent deduction of profits for 10 years. Additional depreciation of 20 per cent in the initial year is proposed to be extended to new assets acquired by power generation companies.

149. For SMEs, the turnover limit for compulsory tax audit of accounts as well as for presumptive taxation is proposed to be raised from ₹ 60 lakh to ₹ 1 crore.

150. In order to augment funds for SMEs, I propose to exempt capital gains tax on sale of a residential property, if the sale consideration is used for subscription in equity of a manufacturing SME company for purchase of new plant and machinery.

151. Considering the shortage of skilled manpower in the manufacturing sector and to generate employment, I propose to provide weighted deduction at the rate of 150 per cent of expenditure incurred on skill development in manufacturing sector in accordance with specified guidelines.

152. In order to reduce transaction costs in the capital markets, I propose reduction in Securities Transaction Tax (STT) by 20 per cent (from 0.125 per cent to 0.1 per cent) on cash delivery transactions.

153. In order to moderate the outgo on profit linked deductions, I propose to extend the levy of Alternate Minimum Tax (AMT) on all persons other than companies, claiming profit linked deductions.

154. I propose to introduce a General Anti Avoidance Rule (GAAR) in order to counter aggressive tax avoidance schemes, while ensuring that it is used only in appropriate cases, by enabling a review by a GAAR panel.

155. I propose a series of measures to deter the generation and use of unaccounted money. To this end, I propose

- Introduction of compulsory reporting requirement in case of assets held abroad.
- Allowing for reopening of assessment upto 16 years in relation to assets held abroad.
- Tax collection at source on purchase in cash of bullion or jewellery in excess of ₹ 2 lakh.
- Tax deduction at source on transfer of immovable property (other than agricultural land) above a specified threshold.
- Tax collection at source on trading in coal, lignite and iron ore.

- Increasing the onus of proof on closely held companies for funds received from shareholders as well as taxing share premium in excess of fair market value.
- Taxation of unexplained money, credits, investments, expenditures etc., at the highest rate of 30 per cent irrespective of the slab of income.

156. My proposals on Direct Taxes are estimated to result in a net revenue loss of ₹ 4500 crore for the year.

Indirect Taxes

157. I shall now turn to indirect taxes. In a slight departure from the previous years, I shall begin with Service Tax.

Service Tax

158. At the end of June this year, this tax will attain adulthood by completing 18 years. It is therefore time to shift gears and accelerate ahead. However, service tax needs to confront two important challenges to sustain the journey. These are:

- The share of services in taxes remains far below its potential. There is a need to widen the tax base and strengthen its enforcement;
- Service Tax law is complex and sometimes avoidably different from Central Excise. We need to bring the two as close as possible in the light of our eventual goal of transition to GST.

I have attempted to address both these issues this year.

159. Last year, I had initiated a public debate on the desirability of moving towards taxation of services based on a negative list. In the debate that continued for the better part of the year, we received overwhelming support for this new concept. It has been perceived both as sound economics and prudent fiscal management.

160. Thus, I propose to tax all services except those in the negative list. The list comprises 17 heads and has been carefully drawn up, keeping in view the federal nature of our polity, the best international practices and our socio-economic requirements.

161. The important inclusions in the negative list comprise all services provided by the government or local authorities, except a few specified services where they compete with private sector. The list also includes pre-school and school education, recognised education at higher levels and approved vocational education, renting of residential dwellings, entertainment and amusement services and a large part of public transportation including inland waterways, urban railways and metered cabs.

162. Agriculture and animal husbandry enjoy a very important place in our lives. Practically all services required for cultivation, breeding, production, processing or

862GI/12-9

marketing up to the stage the produce is sold in the primary markets are covered by the list.

163. In addition to the negative list, there is a list of exemptions which include health care, services provided by charities, religious persons, sportspersons, performing artists in folk and classical arts, individual advocates providing services to non-business entities, independent journalists, and services by way of animal care or car parking.

164. To take financial services to the door steps in rural areas, I have also exempted the services of business facilitators and correspondents to banks and insurance companies.

165. Construction services relating to specified infrastructure, canals, irrigation works, post-harvest infrastructure, residential dwelling, and low-cost mass housing up to an area of 60 sq. mtr. under the Scheme of Affordable Housing in Partnership are also included in the exemptions. To make the life of those who already own an apartment a little easier, I propose to raise the exemption for the monthly charges payable by a member to a housing society from ₹3,000 to ₹5,000.

166. The Year 2012 marks the beginning of the centenary year of Indian cinema. Despite the change in titles from Dada Saheb Phalke's "Raja Harishchandra" to "Ra. One" in recent times, the industry has played a pivotal role in unifying our country in the wake of her considerable diversity. To add to their spirit of celebration, I propose to exempt the industry from service tax on copyrights relating to recording of cinematographic films.

167. Movement towards the negative list will result in reducing nearly 290 definitions and descriptions in the Act to 54, and the exemptions from the existing 88 to 10, of course merging some of the existing exemptions into a revised notification. In terms of number of pages, the law will be shorter by nearly 40 per cent.

168. As a measure of harmonisation between Central Excise and Service Tax, a number of alignments have been made. These include a common simplified registration form and a common return for Central Excise and Service Tax, to be named EST-1. This common return will comprise only one page, which will be a significant reduction from the 15 pages of the two returns at present.

169. Revision Application Authority and Settlement Commission are being introduced in Service Tax to help resolve disputes with far greater ease.

170. Cascading of taxes has been significantly reduced by permitting utilisation of input tax credits in a number of services such as catering, restaurants, hotel accommodation, pandal and shamiana and transport sectors.

171. Place of Supply Rules, that will determine the location where a service shall be deemed to be provided,

are being placed in public domain for stakeholders' comments and shall be notified when the negative list is put into effect. These rules will also provide a possible backdrop to initiate an informed debate to assess all the issues that may arise in the taxation of inter-state services for the eventual launch of GST.

172. I propose to set up a Study Team to examine the possibility of a common tax code for service tax and central excise which could be adopted to harmonise the two legislations as much as possible at the right time.

173. While the problems faced by exporters of goods with respect to taxes on input services was addressed earlier this year, disbursement of taxes that go into the export of services has been an irritant for long. I now announce a new scheme that will simplify refunds without resorting to voluminous documentation or verification. As an added incentive, such refunds will also be admissible for taxes on taxable services that have been exempted.

174. Rules pertaining to the Point of Taxation are also being rationalised, providing greater clarity and removing the irritants. Cenvat credits in a number of areas are being restored. There are a number of other proposals both for the facilitation of business and to check malpractices. I do not wish to take the valuable time of this House for discussing all these proposals.

175. You will notice that most of these measures are guided by the need to move towards a system that is simple, equitable and progressive but are unlikely to make the exchequer richer in any significant way. Looking at our vast commitments and to maintain a healthy fiscal situation, I propose to raise the service tax rate from 10 per cent to 12 per cent, with consequential changes in rates for services that have individual tax rates.

176. My proposals from service tax are expected to yield an additional revenue of ₹18,660 crore. Keeping in mind that the share of services in GDP is 59 per cent, you would agree that the proposed increase is not too harsh. I shall now deal with proposals relating to the other indirect taxes.

177. In the wake of the global financial crisis in 2008-09, the standard rate of excise duty for non-petroleum goods was reduced from 14 per cent to 8 per cent in a phased manner. This rate was raised from 8 per cent to 10 per cent in Budget 2010-11. Given the imperative for fiscal correction, I propose to now raise the standard rate from 10 per cent to 12 per cent, the merit rate from 5 per cent to 6 per cent, and the lower merit rate from 1 per cent to 2 per cent. However, the lower merit rate for coal, fertilisers, mobile phones and precious metal jewellery is being retained at 1 per cent.

178. Large cars currently attract excise duty depending on their engine capacity and length. In keeping with the increase proposed in the standard rate, I propose to enhance the duty from 22 per cent to 24 per cent. In the

case of cars that attract a mixed rate of duty of 22 per cent + ₹15000 per vehicle, I propose to increase the duty and switch over to an *ad valorem* rate of 27 per cent.

179. No change is proposed in the peak rate of customs duty of 10 per cent on non-agricultural goods. Barring a few individual items, the rates below the peak are also being retained.

180. I shall now take up relief proposals for specific sectors - especially those under stress. These have been formulated to stimulate investment and manufacturing growth.

Agriculture and Related Sectors

181. Carrying forward the initiatives taken for agriculture and agro-processing in the previous Budgets, I propose:

- to reduce basic customs duty from 7.5 per cent to 2.5 per cent on:
 - sugarcane planter, root or tuber crop harvesting machine and rotary tiller and weeder;
 - parts for the manufacture of these;
- to reduce basic customs duty from 7.5 per cent to 5 per cent on specified coffee plantation and processing machinery;
- to extend project import benefit to green house and protected cultivation for horticulture and floriculture at concessional basic customs duty of 5 per cent;
- to reduce basic customs duty on some water soluble fertilisers and liquid fertilisers, other than urea, from 7.5 per cent to 5 per cent and from 5 per cent to 2.5 per cent;
- to extend concessional import duty available for installation of Mechanised Handling Systems and Pallet Racking Systems in mandis or warehouses for horticultural produce.

182. Imports of equipment for initial setting up or substantial expansion of fertiliser projects are being fully exempted from basic customs duty of 5 per cent for a period of three years up to March 31, 2015.

Infrastructure

183. In the realm of infrastructure my proposals address some weaknesses in the trioka of power, coal and railways.

184. Domestic producers of thermal power have been under stress because of high prices of coal. I propose to ease the situation by providing full exemption from basic customs duty and a concessional CVD of 1 per cent to Steam coal for a period of two years till March 31, 2014. Full exemption from basic duty is also being provided to the following fuels for power generation:

- Natural Gas and Liquefied Natural Gas; and
- Uranium concentrate, Sintered Uranium Dioxide in natural and pellet form.

Mining

185. Better surveying and prospecting for minerals are essential for improving the productivity and efficiency of our mining sector. I propose to reduce basic customs duty on machinery and instruments for surveying and prospecting from 10 per cent or 7.5 per cent to 2.5 per cent. In addition, full exemption from basic customs duty is being provided to coal mining projects.

Railways

186. Over the next five years, Indian Railways are undertaking two major projects for passenger safety and better service delivery. These are—the installation of Train Protection and Warning System and upgradation of track structure for high speed trains. I propose to reduce basic customs duty on equipment required for their implementation from 10 per cent to 7.5 per cent.

Roads

187. Full exemption from import duty on specified equipment imported for road construction by contractors of Ministry of Road Transport and Highways, NHAI and State Governments is being extended to contracts awarded by Metropolitan Development Authorities.

188. Tunnel boring machines and parts for their assembly are covered by this exemption. I propose to allow their import free of duty without end-use condition.

Civil Aviation

189. India has potential for establishing itself as a hub for third-party Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) of civilian aircraft. To actualize this potential, I propose to fully exempt from basic customs duty parts of aircraft and testing equipment imported for this purpose. As a measure of support to the airline industry, it is also proposed to fully exempt both new and retreaded aircraft tyres from basic customs duty and excise duty.

Manufacturing

190. My proposals for the manufacturing sector that needs support at this juncture, seek to provide relief through cost reduction of raw materials, inputs, components and capital goods.

191. To encourage enrichment of low-grade iron ore, of which we have huge reserves, I propose to reduce basic customs duty on plant and machinery imported for setting up or substantial expansion of iron ore pellet plants or iron ore beneficiation plants from 7.5 per cent to 2.5 per cent. My other proposals relating to the steel sector are as under:

- to reduce basic customs duty on:
 - coating material for manufacture of

862 GI/12-10

electrical steel from 7.5 per cent to 5 per cent,

- nickel ore and concentrate and nickel oxide/hydroxide from 2.5 per cent or 7.5 per cent to Nil.
- to enhance export duty on chromium ore from ₹ 3000 per tonne to 30 per cent ad valorem
- to enhance basic customs duty on non-alloy, flat-rolled steel from 5 per cent to 7.5 per cent.

192. Our textile industry, especially the weaving sector, urgently needs to modernise. I propose to fully exempt automatic shuttle-less looms from basic customs duty of 5 per cent. Similarly, full exemption from basic duty is being accorded to automatic silk reeling and processing machinery as well as its parts. It is also proposed to restrict these exemptions and the existing concessional rate of basic customs duty of 5 per cent only to new textile machinery. Second-hand machinery would now attract basic duty of 7.5 per cent. Other proposals on textiles are:

- to reduce basic customs duty on wool waste and wool tops from 15 per cent to 5 per cent
- to reduce basic customs duty on Titanium dioxide from 10 per cent to 7.5 per cent
- to extend full exemption from basic customs duty to aramid yarn and fabric used for the manufacture of bullet proof helmets

193. Excise duty of 10 per cent is applicable to branded ready-made garments with abatement of 55 per cent from the Retail Sale Price. Along with increase in duty to 12 per cent, I propose to enhance the abatement to 70 per cent. As a result, the incidence of duty as a percentage of the Retail Sale Price would come down from 4.5 per cent to 3.6 per cent.

194. Our MSME sector is fertile ground for the production of low-cost medical devices. In order to provide impetus to this sector, I propose to reduce basic customs duty to 2.5 per cent with concessional CVD of 6 per cent on specified parts, components and raw materials for the manufacture of some disposables and instruments. Full exemption from basic customs duty and CVD is also being extended to specified raw materials for the manufacture of coronary stents and heart valves. These concessions would be subject to actual user condition.

195. My other proposals to support the manufacturing sector include:

- Full exemption from basic customs duty on
 - waste paper,
 - LCD and LED TV panels, and parts of memory card for mobile phones.
- Reduction of basic customs duty on specified raw materials for the manufacture of adult diapers

from 10 per cent or 7.5 per cent to 5 per cent with CVD of 6 per cent and nil special CVD.

196. My attention has been drawn to the plight of a few sectors that are highly labour-intensive and produce items of mass consumption. As a measure of support, I propose to enhance basic customs duty on bicycles from 10 per cent to 30 per cent and on bicycle parts from 10 per cent to 20 per cent.

197. Full exemption from excise duty is currently available to hand-made matches while others attract the standard rate. It is proposed to reduce excise duty on matches manufactured by semi-mechanised units from 10 per cent to 6 per cent.

Health and Nutrition

198. It is proposed to extend concessional basic customs duty of 5 per cent with full exemption from excise duty/CVD to six specified life-saving drugs/vaccines. These are used for the treatment or prevention of ailments such as HIV-AIDS, renal cancer, etc.

199. Protein deficiency among women and children is one of the most common sources of malnutrition in India. I propose to reduce basic customs duty on Soya protein concentrate and isolated soya protein from 30 per cent or 15 per cent respectively to 10 per cent. Simultaneously, excise duty on all processed soya food products is being reduced to the merit rate of 6 per cent.

200. Consumption of iodised salt prevents iodine deficiency and related diseases. I propose to provide a concessional basic customs duty of 2.5 per cent along with reduced excise duty of 6 per cent on iodine.

201. Probiotics are a cost-effective means of combating bacterial infections. It is proposed to reduce the basic customs duty on this item from 10 per cent to 5 per cent.

Environment

202. In order to fully realise our potential in the realm of solar energy, solar thermal projects need encouragement. I propose to fully exempt plant and equipment etc. for the initial setting up of such projects from special CVD.

203. Concessions have already been provided for encouraging the consumption of energy-saving devices. I propose to fully exempt a coating chemical used for compact fluorescent lamps, from basic customs duty. Excise duty on LED lamps is also being reduced to 6 per cent.

204. Specified parts required for the manufacture of hybrid vehicles enjoy full exemption from basic customs duty and special CVD with concessional excise duty/CVD of 6 per cent. This concession is being extended to specified additional items and lithium ion batteries imported for the manufacture of battery packs for supply to electric or hybrid vehicle manufacturers.

205. One of the primary drivers of the current account deficit has been the growth of almost 50 per cent in imports of gold and other precious metals in the first three quarters of this year. I have been advised to strengthen the steps already taken to check this trend for better results. I propose to increase basic customs duty on standard gold bars; gold coins of purity exceeding 99.5 per cent and platinum from 2 per cent to 4 per cent and on non-standard gold from 5 per cent to 10 per cent. In sync with these, basic duty on gold ore, concentrate and dore bars for refining is being enhanced from 1 per cent to 2 per cent. On the excise side, duty on refined gold is being increased in the same proportion from 1.5 per cent to 3 per cent.

206. In order to prevent round-tripping, it is proposed to impose basic customs duty of 2 per cent on cut and polished, coloured gem stones at par with diamonds.

Additional Resource Mobilisation

207. I shall now take up my proposals on "demerit" goods. I propose to increase basic excise duty on cigarettes of more than 65mm length by adding an *ad valorem* component of 10 per cent to the existing specific rates. The *ad valorem* duty would be chargeable on 50 per cent of the Retail Sale Price declared on the pack.

208. I also propose to carry out a nominal increase in basic excise duty on hand-rolled *bidis* from ₹8 to ₹10 per thousand and on machine-rolled *bidis* from ₹19 to ₹21 per thousand. The existing exemption available to hand-rolled *bidis* for clearances up to 20 lakh *bidis* per annum is being retained.

209. Pan masala, gutkha, chewing tobacco, unmanufactured tobacco and zarda scented tobacco in pouches are leviable to excise duty under the compounded levy scheme. The rates of duty specified per packing machine for these items are being stepped up taking into account improvements in the efficiency of machines used by this industry.

210. Crude petroleum oil produced in India attracts a cess of ₹2,500 per metric tonne under the Oil Industries Development Act. This rate was last revised in Budget 2006-07. As a measure of indexation, I propose to increase the rate of cess to ₹4,500 per metric tonne.

211. Completely Built Units of large cars/ MUVs/ SUVs having engine capacity above a prescribed threshold and whose value exceeds US dollar 40,000 per vehicle are permitted for import without type approval. Basic customs duty on such vehicles is being enhanced from 60 per cent to 75 per cent *ad valorem*.

Rationalisation Measures

212. Packaged cement, whether manufactured by mini-cement plants or others, attracts differential excise duty depending on the Retail Sale Price per bag. It is proposed to prescribe a unified rate of 12 per cent + ₹ 120 PMT for non-mini cement plants and 6 per cent + ₹ 120

PMT for mini-cement plants. It is proposed to charge this duty on the Retail Sale Price less abatement of 30 per cent.

213. The House would recall that I had re-introduced a levy of excise duty of 1 per cent on branded precious metal jewellery in the last Budget. As a measure of rationalisation, I propose to include jewellery, not bearing a brand name, under its ambit. However, to simplify its operation and minimise its impact on small artisans and goldsmiths, I propose:

- to charge this duty on tariff value equal to 30 per cent of the transaction value;
- to extend small-scale exemption up to annual turnover not exceeding ₹ 1.5 crore for units having a turnover below ₹ 4 crore in the previous year;
- to compute turnover on the basis of tariff value; and
- to place the onus of registration and payment on the person who gets jewellery manufactured on job-work.

214. I propose to fully exempt branded silver jewellery from excise duty.

215. Building of commercial vehicle bodies is currently exempt from excise duty. In lieu of this duty, a specific rate of ₹10,000 is being charged on chassis in addition to the applicable *ad valorem* duty. This duty structure is regressive. It is proposed to convert the specific component of duty to an *ad valorem* rate of 3 per cent.

216. In the last Budget, excise duty exemption on ships and vessels including dredgers was withdrawn. Accordingly, CVD of 5 per cent became leviable on their imports. As the intention was not to levy this duty on the import of foreign-going vessels, I propose to exempt such vessels from CVD retrospectively. However, to ensure that ships, vessels and dredgers manufactured in India do not face disability vis-a-vis foreign-going ships converting into coastal vessels, necessary safeguard is being provided.

Baggage Allowance

217. Baggage allowance for Indians travelling abroad was last revised in 2004. I propose to increase the duty-free allowance for eligible passengers of Indian origin from ₹ 25,000 to ₹ 35,000 and for children of up to 10 years from ₹ 12,000 to ₹ 15,000.

218. My proposals relating to Customs and Central excise are estimated to result in a net revenue gain of ₹ 27,280 crore for a full year.

219. My proposals on Direct Taxes are estimated to result in a net revenue loss of ₹ 4500 crore for the year. Proposals relating to Indirect Taxes are estimated to result in a net revenue gain of ₹ 45,940 crore, leaving a net gain of ₹ 41,440 crore in the Budget.

220. For the Indian economy, this was a challenging year. A number of global and domestic factors militated against the growth that had revived in the last two years. But India has thrived under challenges and India will do so now. In the middle of every crisis, there is also an opportunity. It is an opportunity to re- think, re-assess and make way for new ideas and policies. It is in this spirit that I approached the Budget of this year. The aim is to create an enabling atmosphere for corporates, farmers, entrepreneurs and workers to take initiatives for robust

growth. The aim is also to ensure that the benefits of growth reach all sections of population. India stands on the brink of a major resurgence. Whether or not today's announcements make tomorrow morning's headlines matters little, as long as they help in shaping the headlines that describe India a decade from now.

Madam Speaker, with these words, I commend the Budget to the House.

SHAKTIKANTA DAS, Addl. Secy. (Budget)